वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 1987-88

सत्यमेव जयते

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

New Delhi,
May 3, 1988.

Dear Shri Sathe,

It has given me great pleasure to receive a letter from the first Indian Post Master functioning in our Post Office at Dakshin Gangotri, Antarctica.

Please convey to him thr... the new channel established with that post offi... felicitations ... wishes. ... neering ... expe... e of t... nisior ... aying

कार्य प्रगति Activities-1988-89

भारतीय डाक विभाग Department of Pos

विषय सूची

पुनरीक्षा	1
डाक प्रचालन में सुधार	3
मानव संसाधन	10
डाक वित	15
कार्य प्रगति	21
1985 से अब तक	22

Contents

Overview	23
Improving Postal Operations	25
Human Resources	32
Postal Finances	38
Activities	44
Since 1985	45
Statistical Supplements	47

E R R A T A

Page No.	Para	Line	Col.	For	Read
25	Expansion of Postal Postal Network	20	1	Whichare to opened	Which are to be opened
		6	2	is not less than 1500 in hilly, back-ward & tribal areas	is not less than 1500 in hilly, backward & tribal areas and 3000 in normal rural areas
33	Staff strength (Graph relating to Gazetted/- Non-Gazetted and Extra-Departmental staff)			Colour Code Red - Non Gazetted Green - Extra Depart-mental	Colour Code Red - Extra Departmental Green - Non Gazetted
44	Activites	27	2	5 years	5½ years

पुनरीक्षा

पिछले दशक में विश्व भर में संचार प्रौद्योगिकी में बड़े परिवर्तन हुए हैं। मंत्रालय का दूरसंचार विभाग जहां इन नाटकीय परिवर्तनों को आत्मसात् करने की कोशिश कर रहा है, वहां डाक विभाग द्वारा प्रदान की गई पारंपरिक डाक सेवाएं इस देश के जन समुदाय के लिए प्रासंगिक रहीं। व्यावसायिक घरानों, कानूनी मामलों और शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए डाक-संचार की प्रासंगिकता और महत्व को उच्च औद्योगिक संस्थाओं ने भी पूरी तरह स्वीकार किया है। ऐसी संभावना है कि आने वाले अनेक दशकों तक डाकघर इस देश के अभिव्यक्तिशील माध्यमों का मुख्य आधार बने रहेंगे। भारत का छियानवे प्रतिशत क्षेत्र ग्रामीण है और हमारी 77 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। हम सब के लिए डाक सेवा संदेश भेजने का मुख्य जरिया है और आने वाले समय में भी रहेगा। शहरों में काम करने वाले, व्यापार, और वाणिज्य से जुड़े इसके उपभोक्ता डाक सेवा को अपना मानव मित्र मानते हैं।

संसाधनों की सीमितता के बावजूद, डाक विभाग ने उस जनसाधारण को सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने नेटवर्क का विस्तार करना जारी रखा है जिसे डाकघर जाने के लिए पहले मीलों चलना पड़ता था। डाकघर खोलने के मानदंडों को उदार बनाया गया है और ग्राम पंचायत, जो विकेन्द्रीकृत प्रशासन की आधारभूत इकाई है, डाक सुविधाएं प्रदान करने का केन्द्र बिन्दु बन गई हैं। उन ग्राम पंचायत वाले ग्रामों में जहां तत्काल डाकघर नहीं खोला जा सकता, डाक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'पंचायत डाक सेवक', नामक एक नवीन प्रणाली शुरू की गई है। पंचायत डाक सेवक, ग्राम पंचायतों के कर्मचारी होते हैं लेकिन डाक संबंधी कार्य करने के लिए इन्हें डाक विभाग द्वारा पारिश्रमिक दिया जाता है।

डाक सेवाएं प्रदान करना डाक विभाग का एकाधिकार है और फलस्वरूप पत्र चाहे एक ही शहर के भीतर भेजने हों या एक शहर से दूसरे शहर को भेजने हों या फिर विदेश भेजने हों, समान दर पर डाक सुविधाएं प्रदान करना इसका दायित्व बन जाता है। अनेक प्राइवेट कुरिअरों ने ऊंची दर पर चुने हुए उपभोक्ताओं को शहर के भीतर या एक शहर से दूसरे शहर के लिए प्रीमियम स्पीडी सर्विस प्रदान कर आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद कारोबारी क्षेत्र को आकर्षित करने की कोशिश की है तथा डाक सेवा को अपेक्षाकृत अधिक खर्चीली लंबी दूरी की डाक लाने-ले जाने और वितरण सेवाओं का संचालन करने के लिए छोड़ दिया है। डाक विभाग ने इस चुनौती का जोरदार उत्तर दिया और 'स्पीड पोस्ट' नामक एक प्रीमियम सेवा शुरू की। इस सेवा के अंतर्गत डाक-मद का 24 घंटों के अन्दर वितरण को जाता है। देश में 50 शहरों के लिए यह सेवा उपलब्ध है। इस सेवा का मनीआर्डर भेजने के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे प्रयास भी किए गए कि डाक प्रबंधक मुख्य उपभोक्ताओं के अधिक निकट रहकर काम करें ताकि आज की डाक सेवा उनकी आवश्यकताओं को समझने और उनका पूर्वानुमान लगाने में सक्षम हो। डाक सेवा भी एफ. ए. एक्स., उपग्रह संचार प्रणाली द्वारा प्रदान की गई तकनीकी सुविधाओं को अपनाने और डाक का मशीनें द्वारा निपटान करने के लिए स्वयं को इसके अनुकूल बना रही है। इन तरीकों से सेवाओं में तेजी ही नहीं बल्कि लागत भी कम आएगी और विभाग को जन-साधारण के लाभ के लिए अपनी डाक-मदों और सेवाओं के मूल्य को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी।

विभाग के वित्तीय स्रोत चिन्ता का विषय रहे हैं। यद्यपि सरकार ने डाक सेवा को वित्तीय दृष्टि से फायदे-मंद या संसाधन जुटाने वाली संस्था कभी नहीं माना है। इस सेवा से आशा यह की जाती है कि यह आत्म-निर्भर बने या अपने घाटे को एक स्वीकार्य सीमा के भीतर बनाए रखे। मूल्यवृद्धि के इस युग में, विशेषकर डाक सेवा जैसे अत्यधिक श्रम साध्य संगठन में कार्मिक लागत तथा डाक सामग्री और सेवाओं के मूल्य को उनकी वास्तविक लागत से कम रखने की सुविचारित नीति को देखते हुए यह एक अत्यंत कठिन कार्य है। फिर भी, डाक सेवा ने 1986-87 में हुए 2160 मिलियन रूपये के घाटे को कम कर 1987—88 में 1900 मिलियन रूपये करने में सफलता पाई है। सरकार, योजना आयोग और वित्त आयोग ने सातवीं और आठवीं योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने की दृष्टि से राजस्व घाटे को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसलिए, डाक विभाग डाक-कार्य में हुई वृद्धि को काफी हद तक बढ़ी हुई उत्पादकता के माध्यम से पूरा करके निरन्तर लागत ही नहीं घटाता रहेगा वरन् डाक सेवाओं के उपभोक्ताओं पर अतिशय भार डाले बिना धीरे-धीरे मूल्य और लागत के बीच अन्तर को भी क्रमबद्ध रूप से कम करेगा।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मात्र प्रौद्योगिकी और वित्तीय साधनों की सुलभता ही डाक संचालन का कार्य नहीं कर सकती। इसके लिए डाक सेवा को अपने लगभग 600 हजार कर्मचारियों के प्रयासों पर निर्भर करना होगा। इस विभाग के पुरूष और महिला कर्मचारी लोक सेवा की अपनी दीर्घ परंपरा के प्रति कटिबद्ध रहे हैं, किन्तु वे यह मानते हैं कि डाक सेवा को जिस प्रतियोगी वातावरण का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए आवश्यक यह है कि वह अपने उपभोक्ताओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए नए-नए परिवर्तन लाए और कड़ी मेहनत करे। निरन्तर विचार-विमर्श तथा विचारों के आदान-प्रदान द्वारा और सामूहिक सौदेबाजी में रूखापन दूर करके डाक सेवा, उपभोक्ता केंद्रित सेवा का सूत्रपात करने, नई प्रौद्योगिकी की शुरूआत करने और लागत पर नियंत्रण रखने की अपनी बढ़ती हुई वचनबद्धता के प्रति डाक उपभोक्ताओं का समर्थन प्राप्त करने में सफल होगी।

अपनी सभी बाधाओं के बावजूद डाक सेवा ने इस देश की एक अत्यंत आधारभूत लोक सेवा, कुशलता और ईमानदारी से प्रदान करने की निरंतर कोशिश की है। परिवर्तन और नवीन पद्धतियों के माध्यम से लोक सेवा की यह मूल परंपरा समृद्ध होती रहेगी।

डाक प्रचालन में सुधार

लक्ष्य

डाक विभाग का इस वर्ष यह प्रयास रहा है कि सेवा की गुणवत्ता में सुधार व इसका विस्तार किया जाए तथा उपभोक्ता को अधिक से अधिक संतुष्टि प्रदान की जाए। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पूरी प्रचालन व्यवस्था को साधनयुक्त बनाया जा रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मौजूदा नेटवर्क को ग्रेस बनाया गया और उपभोक्ताओं को पूरी तरह संतुष्ट करने तथा सेवा को ग्रहय बनाने के लिए अनेक नए उपाय किए गए।

डाक नेटवर्क का विस्तार

31.3.1988 को डाक नेटवर्क के अंतर्गत 1,44,829 डाकघर थे जिनमें 1,28,829 ग्रामीण क्षेत्रों में और 16,000 शहरी क्षेत्रों में थे। प्रत्येक डाकघर औसतन 22.69 वर्ग कि. मी. क्षेत्र तथा 4731 लोगों को सेवा प्रदान करता है। विकास के इस स्तर को देखते हुए, देश, विश्व डाक संघ (यू. पी. यू.) द्वारा अपनाए

डाकघरों की संख्या

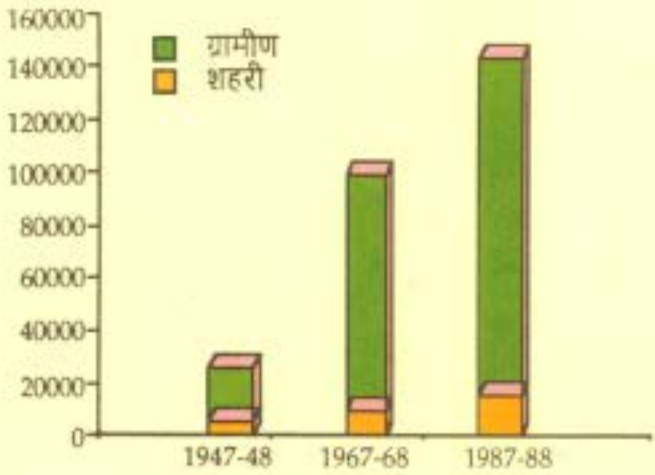

गए मानदंड पूरे करता है जिनमें यह व्यवस्था है कि औसतन 20 से 40 वर्ग कि. मी. क्षेत्र के लिए अथवा 3000 से 6000 तक की जनसंख्या के लिए एक डाकघर होना चाहिए। देश में कुल 4,81,757 लेटर बॉक्स थे जिनमें से 4,01,156 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 80,601 शहरी क्षेत्रों में थे।

देश की सातवीं योजना के दौरान, ग्रामीण क्षेत्रों में 6,000 नए डाकघर खोलने का विचार है। इनमें से अधिकांश डाकघर 1988-89 और 1989-90 में खोले जाने हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोलने के मानदंडों को 19.12.87 से उदार बनाया है। संशोधित मानदंड इस प्रकार हैं:

- ऐसा ग्राम समूह जिनकी एक ग्राम पंचायत या ग्राम परिषद हो एक डाकघर का पात्र होगा बशर्ते कि (क) उस ग्राम समूह की कुल जनसंख्या सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 और पर्वतीय, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में 1,500 से कम न हो और (ख) उस ग्राम समूह के अंतर्गत कोई डाकघर न हो।
- सामान्यत: मौजूदा डाकघर से 3 कि. मी. की दूरी के भीतर कोई नया डाकघर नहीं खोला जाएगा। तथापि, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए इस प्रतिबंध से छूट होगी।
- सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्रस्तावित डाकघर का प्रत्याशित राजस्व उसकी लागत का 33.33 प्रतिशत से कम और पर्वतीय, जनजातीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सेवाओं की उपलब्धता विकेन्द्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप डालने के उद्देश्य से संचार मंत्री ने 24.2.88 को संसद में घोषणा की कि —

> माननीय, सदस्यों और आम जनता की जोरदार मांग को ध्यान में रखते हुए अगले दो वर्षों में क्षेत्र 74,000 पंचायत वाले ग्रामों में से प्रत्येक में डाक सुविधाओं के लिए सरकार एक व्यापक कार्यक्रम चलाना चाहती है।

इस नीति के अनुपालन के लिए डाक विभाग ने 'पंचायत डाक सेवक योजना' नामक एक योजना प्रारंभ की है।

डाक

डाक परियात में निरन्तर तेजी से वृद्धि होती जा रही है। वर्ष के दौरान विभाग ने लगभग 500 करोड़ डाक वस्तुओं का निपटान किया।

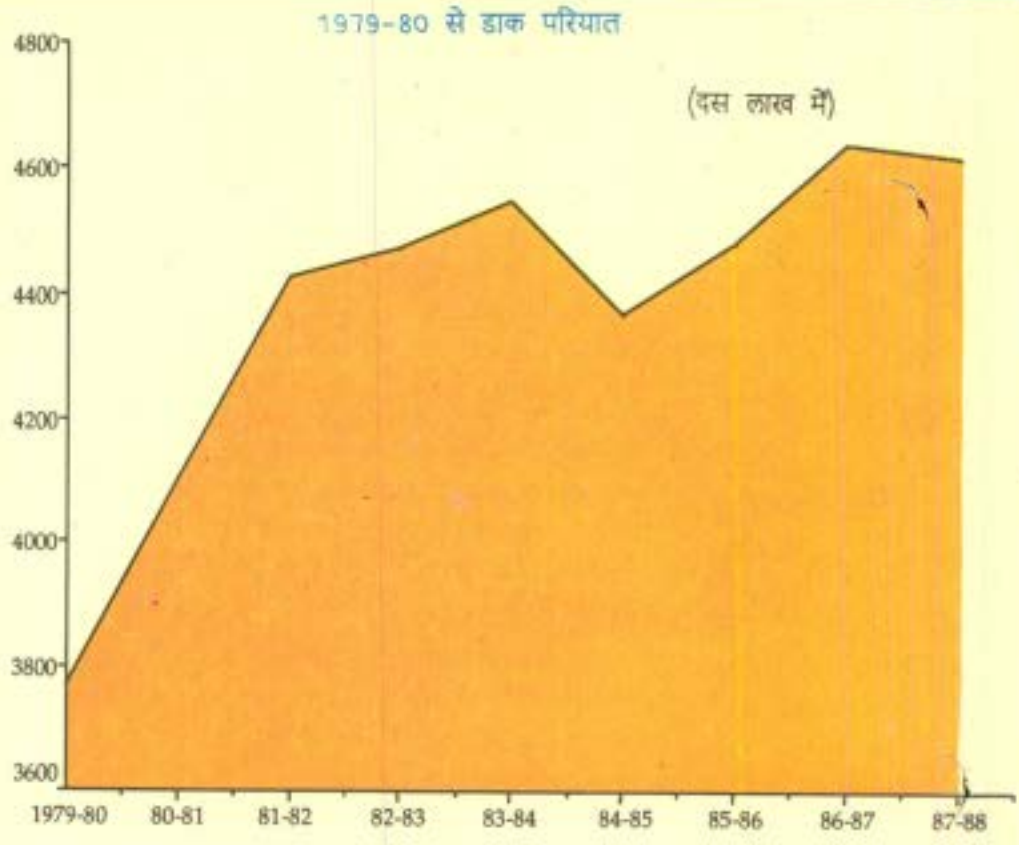

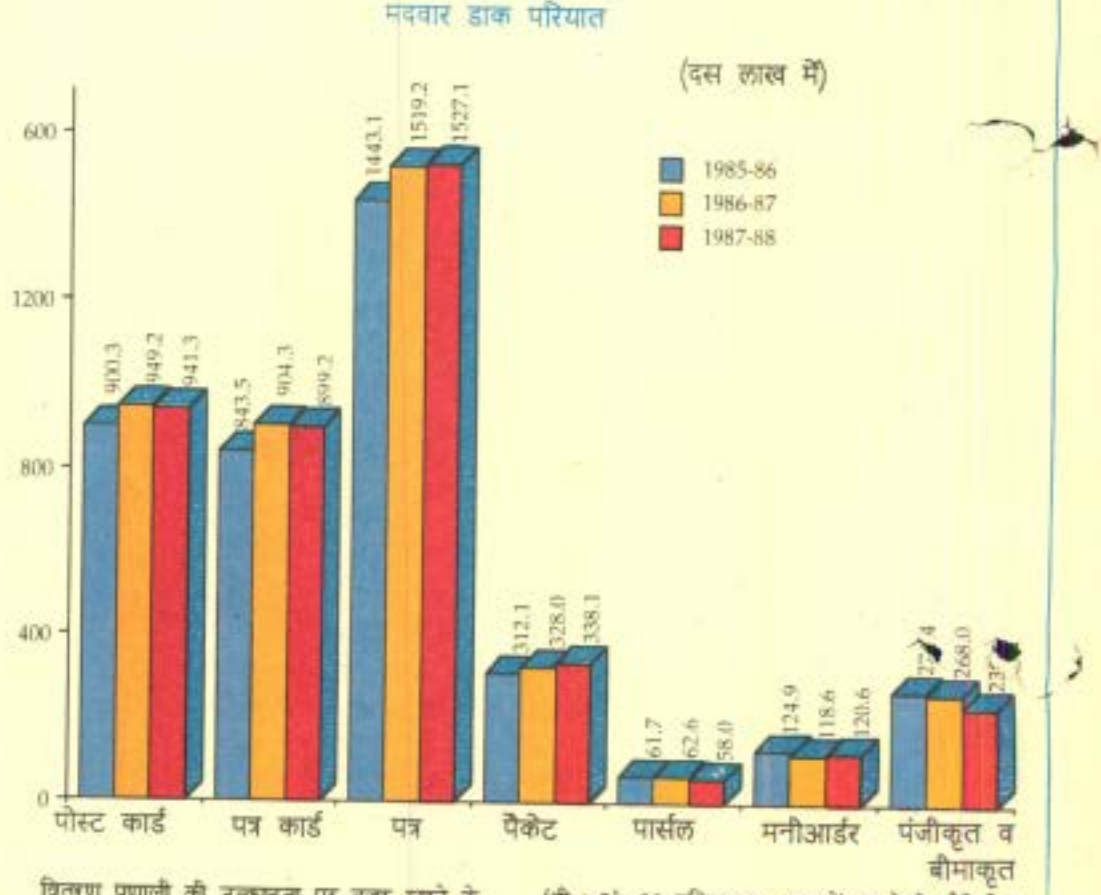

1979-80 से डाक परियात

मदवार डाक परियात

वितरण प्रणाली की उत्कृष्टता पर नज़र रखने के लिए राष्ट्रीय आधार पर व्यावहारिक रूप में डाक वितरण को परखने की प्रक्रिया शुरू की गई । 23 प्रतिशत डाक का वितरण उसके डाक में डालने के दूसरे दिन हो जाता है (डी + 1), 25 प्रतिशत का डाक में डालने के तीसरे दिन (डी + 2), 29 प्रतिशत का डाक में डालने के चौथे दिन (डी + 3), और शेष 23 प्रतिशत का डाक में डालने के पांचवे दिन (डी + 4) वितरण हो जाता है । इन प्रतिशतों से वितरण के लिए कुल डाक की स्थिति सामने आ जाती है न कि मात्र उन डाक मदों की जिन्हें डी + 1 या डी + 2

आदि में वितरित किया जा सकता है ।

अब विभाग अपने परंपरागत प्रचालनों के कुछ क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है । जहां पत्र डाक को लाने ले जाने पर विभाग का एकाधिकार है वहां दस्तावेजों और पार्सलों के लाने-ले जाने में प्राइवेट कूरियर भी आगे आ गए हैं । लम्बे समय से प्रचलित अपनी परंपराओं और डाक के पारेषण तथा वितरण के क्षेत्र में अनुभव का प्रयोग करते हुए विभाग ने 1986 में 'स्पीड पोस्ट' नामक एक गारंटीशुदा वितरण सेवा प्रारंभ की है जो सस्ती और प्राइवेट कूरियर सेवाओं का अधिक विश्वसनीय विकल्प है । आलोच्य वर्ष के दौरान, स्पीड पोस्ट सेवा में 23 और केन्द्र शामिल किए गए जिससे देश में इन केन्द्रों की संख्या 37 हो गई है । इस सेवा में मनीआर्डर भी शामिल किए गए हैं जो मामूली अतिरिक्त खर्च से एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जा सकते हैं । स्पीड पोस्ट सेवा के परियात विश्लेषण से पता चलता है कि इसे उपभोक्ताओं ने स्वीकार किया है और इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है । इस प्रकार अप्रैल, 1987 में 14 स्पीड पोस्ट सेवा केंद्रों से 68,264 वस्तुओं के परियात से यह सेवा प्रारंभ करके अब यह परियात मार्च, 1988 में 37 केन्द्रों और 7 पिस्तार काउन्टरों से 1,30,662 वस्तुओं तक पहुंच गया था, जिसका अर्थ यह है कि इसमें लगभग सौ प्रतिशत वृद्धि हुई है । अलग-अलग केन्द्रों के परियात आंकड़ों से भी पता चला है कि स्पीड पोस्ट सेवा की ग्राहयता और उसके प्रयोग में अधिक वृद्धि हुई है ।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस स्पीड पोस्ट सेवा को 20 देशों के साथ जोड़ा गया ।

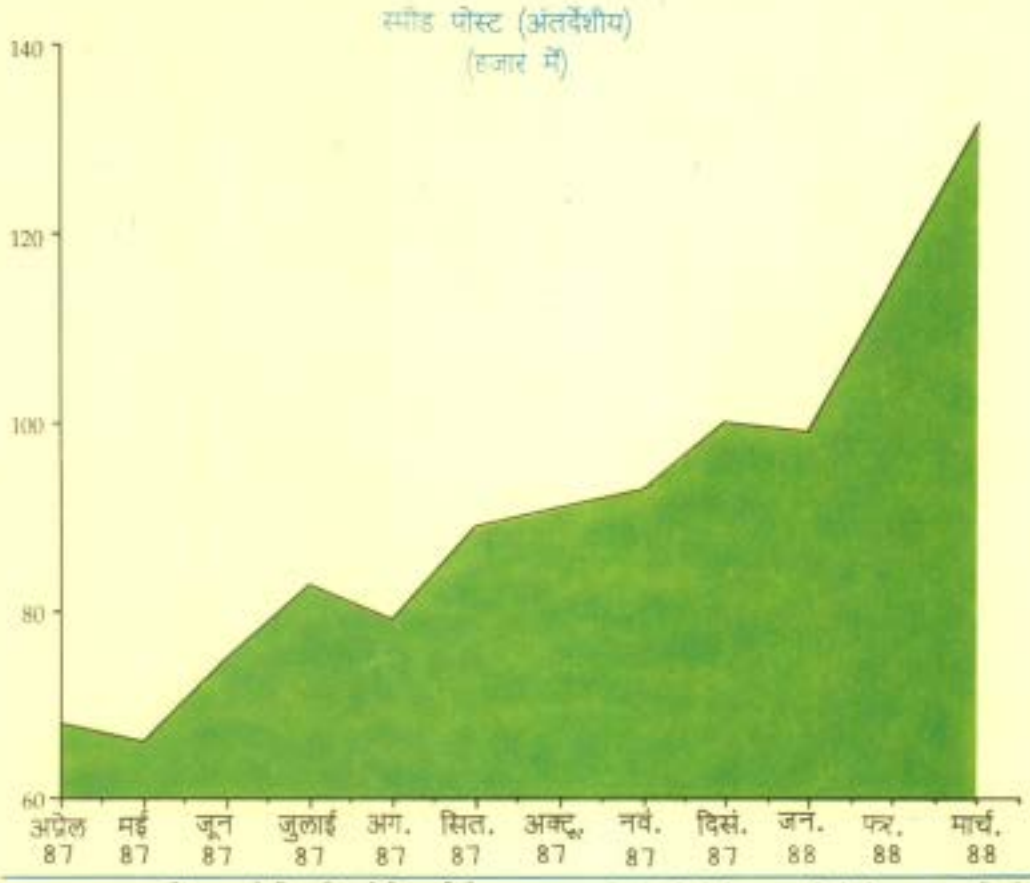

डाक परिसर

डाक प्रचालन में सुधार के लिए जिन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना है उनमें एक क्षेत्र है डाकघरों के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किये गए विस्तृत भवन उपलब्ध कराना । इस प्रयोजन के लिए 1987-88 के दौरान, 30 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई थी । 109 डाकघर और डाक कार्यालय भवनों का निर्माण प्रारंभ किया गया तथा 68 डाकघर भवनों का निर्माण-कार्य पूरा हो गया है । अन्य 264 डाकघर और डाक कार्यालय भवन निर्माण के विभिन्न चरणों में थे । इस अवधि के दौरान, 283 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण-कार्य प्रारंभ किया गया था एवं 952 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण-कार्य पूरा किया गया था तथा 950 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण कार्य चल रहा था । पुनरीक्षाधीन वर्ष के अन्त में, 25,866 विभागीय डाकघरों में से 3179 या कुल डाकघरों के 12.29 प्रतिशत डाकघर विभागीय भवनों में काम कर रहे थे ।

तकनीकी विकास

विभाग उपभोक्ता सेवाओं में सुधार और समुचित क्षेत्रों में तकनालॉजी का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाने की संभावना के प्रति सजग है । तकनालॉजी के प्रयोग के लिए जिन दो विस्तृत क्षेत्रों को चुना गया है वे हैं —आंतरिक कार्य संचालन और जनता तथा कार्यालयों के बीच का क्षेत्र । कार्यालयों में आंतरिक कार्य संचालन के लिए इसके साथ ही साथ बेंगलूर, मद्रास और दिल्ली में कंप्यूटरीकरण भी प्रारंभ कर दिया

गया है । बेंगलूर में स्थापित कंप्यूटर डाक जीवन बीमा का कार्य करता है और मद्रास वाले से मनीआर्डर पेयरिंग का कार्य लिया जा रहा है । दिल्ली में कंप्यूटरों का प्रयोग मनीआर्डर पेयरिंग, अंतर्राष्ट्रीय डाक लेखे और बचत बैंक कार्य के लिए किया जा रहा है । इन मुख्य परियोजनाओं के अनुभव के आधार पर विभाग के आंतरिक कार्य को गतिशील बनाने के लिए आधुनिक तकनालॉजी के अधिक उपयोग हेतु योजनाएं बनाई जा रही हैं ।

तेजी से डाक-टिकट विरूपित करने वाली मशीनों को देश में ही तैयार किया गया है और इस वर्ष ऐसी 40 मशीनें व्यस्त डाकघरों को सप्लाई की गई हैं । तेजी से काम करने वाली इन मशीनों से हाथ से काम लेने का नित्यश्रम ही दूर नहीं हुआ बल्कि हाथ से लगाई जाने वाली मौजूदा मुहरें भी हट गई हैं । ये मुहरें शीघ्र घिस जाती हैं और इनकी छाप भी धब्बेदार और अस्पष्ट होती है । चूंकि हाथ की मुहरों का प्रयोग छोटे डाकघरों में जारी रहेगा अत: केन्द्रीय कार्यशाला पोस्टल मशीन नई दिल्ली द्वारा प्रायोगिक आधार पर हाथ की मुहरों में सुधार करने के तरीके विकसित किए गए और सुधरी हुई बीस मुहरों और सीलों को दिल्ली में आजमाकर देखा जा रहा है । प्रयोग के सफल सिद्ध होने पर इन मुहरों का निर्माण नई दिल्ली और अलीगढ़ में प्रारंभ कर दिया जाएगा । मुहरों में प्रयोग किए जाने वाली स्टील के स्थान पर पॉलीमर का उपयोग संभवत्या अधिक सस्ता, टिकाऊ और अच्छे छाप देने वाला सिद्ध होगा । स्टील के स्थान पर पॉलीमर वाली हाथ की 136 मुहरें फ्रांस से आयात की गई थीं और उनका चुनिंदे डाकघरों में परीक्षण किया जा रहा है । उनका निर्माण देश में ही करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

500 करोड़ वस्तुओं के कुल परिवात का 18 से 20 प्रतिशत चार महानगरीय शहरों में आत-जात है । महानगरीय डाक को हाथ से निपटाना बराबर कठिन होता जा रहा है । महानगरीय शहरों में स्वचालित डाक प्रक्रिया के प्रारंभ करने के पहले चरण में बम्बई को चुना गया है । बम्बई के लिए परियोजना को मंजूरी दे दी गई है और इस परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए शीघ्र ही विश्व भर से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी ।

कार्यालय और जनता के मध्य चलने क्षेत्र में विभाग ने एक माइक्रो प्रोसेसर आधृत मशीन प्रारंभ करने में सफलता प्राप्त कर ली है जो एक ही काउन्टर से पार्सल, मनीआर्डर, पंजीकृत पत्र, मूल्यदेय वस्तुओं के साथ-साथ स्पीड पोस्ट वस्तुओं की बुकिंग भी कर सकती है । प्रारंभिक परीक्षणों के बाद ऐसी मशीनों का शीघ्र ही डाकघरों में व्यापक प्रयोग किए जाने की संभावना है । वस्तुओं का भार और भार के हिसाब से उचित डाक प्रभार दर्शाने वाली डिजीटल भार मापक मशीनें भी विकसित की गई हैं । इन साधनों से डाक काउन्टरों पर उपभोक्ता सेवाओं में पर्याप्त सुधार होगा ।

कार्यालय और जनता के मध्य चलने क्षेत्र में विभाग ने एक माइक्रो प्रोसेसर आधृत मशीन प्रारंभ करने में सफलता प्राप्त कर ली है जो एक ही काउन्टर से पार्सल, मनीआर्डर, पंजीकृत पत्र, मूल्य देय वस्तुओं के साथ-साथ स्पीड पोस्ट वस्तुओं की बुकिंग भी कर सकती है । प्रारंभिक परीक्षणों के बाद ऐसी मशीनों का शीघ्र ही डाकघरों में व्यापक प्रयोग किए जाने की संभावना है । वस्तुओं का भार और भार के हिसाब से उचित डाक प्रभार दर्शाने वाली डिजिटल भार मापक मशीनें भी विकसित की गई हैं । इन साधनों से डाक काउन्टरों पर उपभोक्ता सेवाओं में पर्याप्त सुधार होगा ।

बचत बैंक

जनता ने डाकघर बचत बैंक में अपनी आस्था बरकरार रखी है । यह देश में सबसे बड़ा बचत बैंक है जिसका प्रचालन 1,44,084 डाकघरों के विस्तृत नेटवर्क के जरिए हो रहा है । जमाकर्त्ताओं को बेहतर सेवाएं सुलभ कराने और प्रचालन में मितव्ययिता लाने के उद्देश्य से वर्ष 1987-88 में विभिन्न उपाय किए गए जो इस प्रकार हैं:

— अब संचयी सावधि जमा खाते समयपूर्व बन्द करने की अनुमति दे दी जाती है और इसमें अधिकतम राशि की बात बीच में नहीं आती ।

— बचत बैंक खाते में की जा सकने वाली जमा की अधिकतम सीमा एकल खाते में 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए तथा संयुक्त खाते में 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए कर दी गई है ।

— निम्न चयन ग्रेड तथा उससे उच्च ग्रेड के डाकघरों को व्यक्तिगत बचत खाते बन्द करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है । इससे जनता को बेहतर सुविधाएं सुलभ होंगी तथा व्यक्तिगत खातों को बन्द करने में समय भी कम लगेगा ।

आयकर दाताओं के लाभ के लिए 1.4.87 से एक राष्ट्रीय बचत योजना चालू की गई है । इस योजना के अंतर्गत किसी एक खाते में जमा की गई सम्पूर्ण राशि जो 1987-88 वर्ष में 30,000 रुपये से अधिक न हो, आयकर से मुक्त है ।

15.8.87 से डाकघर मासिक आय खाता योजना नामक एक नई योजना चालू की गई है । यह योजना सेवानिवृत्त हो रहे व्यक्तियों, पेंशनरों, और अन्य व्यक्तियों जो नियमित मासिक आय चाहते हों, उनके लिए एक आकर्षक योजना है । यह योजना केवल वैयक्तिक आधार पर लागू होगी । इस योजना में न्यूनतम जमा 5000/- रु. या इसके गुणकों में होगी । एकल खाते में अधिकतम 2 लाख रुपये और संयुक्त खाते में अधिकतम 4 लाख रुपये जमा किए जा सकते है । इसकी परिपक्वता अवधि छ: वर्ष है तथा 12 प्रतिशत की दर से मासिक रूप से ब्याज दिया जाता है ।

200/- रु. के इंदिरा विकास पत्र का एक नया मूल्य-

वर्ग भी चालू किया गया है।

प्रधान डाकघरों को स्थानीय शोधन-गृहों (लोकल क्लियरिंग हाऊस) के पूर्ण सदस्य के बतौर नामांकित करने का कार्य 1987-88 में भी जारी रहा। 202 प्रधान डाकघर स्थानीय शोधन गृहों के पूर्ण सदस्य बन गए हैं।

सभी किस्मों के बचत-खातों की संख्या

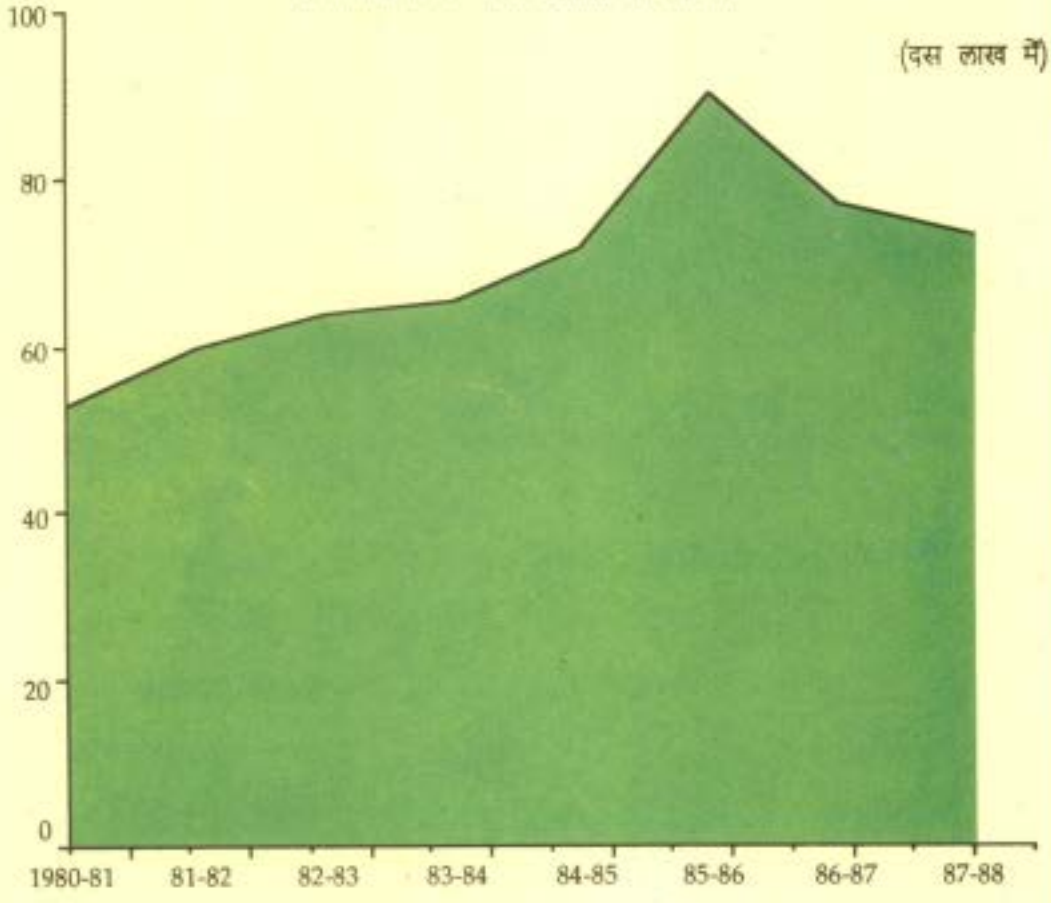

सभी प्रकार की बचतों में बकाया इतिशेष

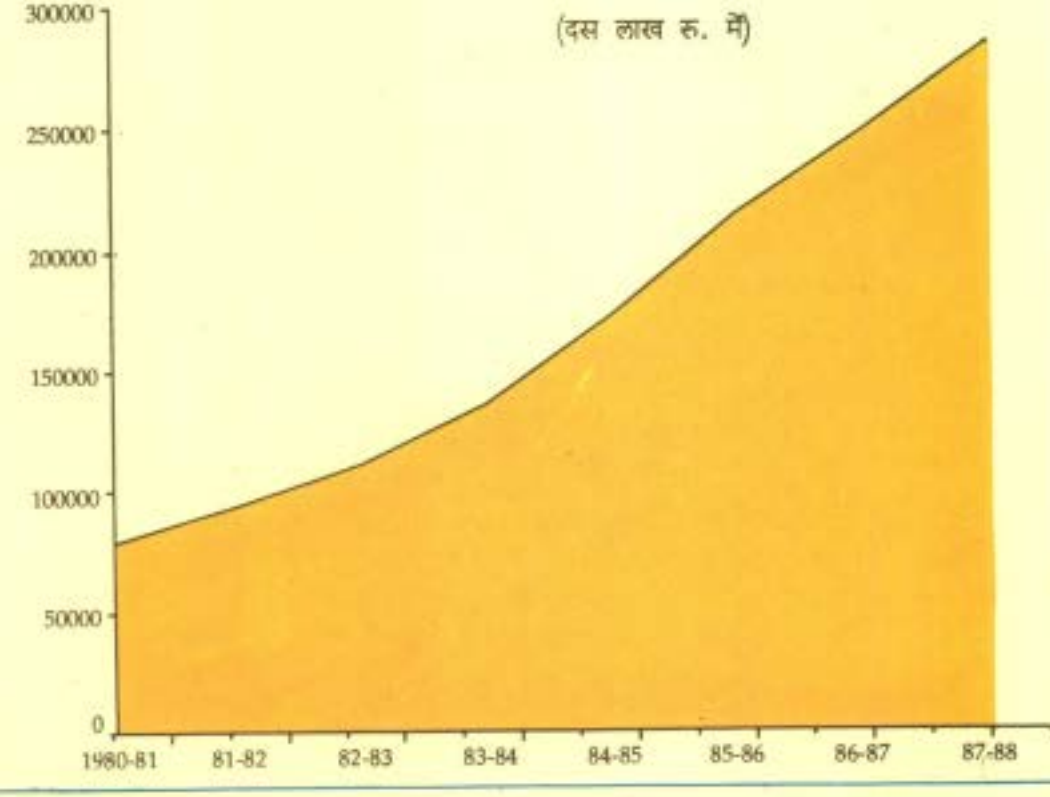

डाक जीवन बीमा

बचत बैंक के समान ही, डाक जीवन बीमा में भी पालिसियों की संख्या के साथ प्रति पालिसी प्रीमियम में भी लगातार वृद्धि हुई है।

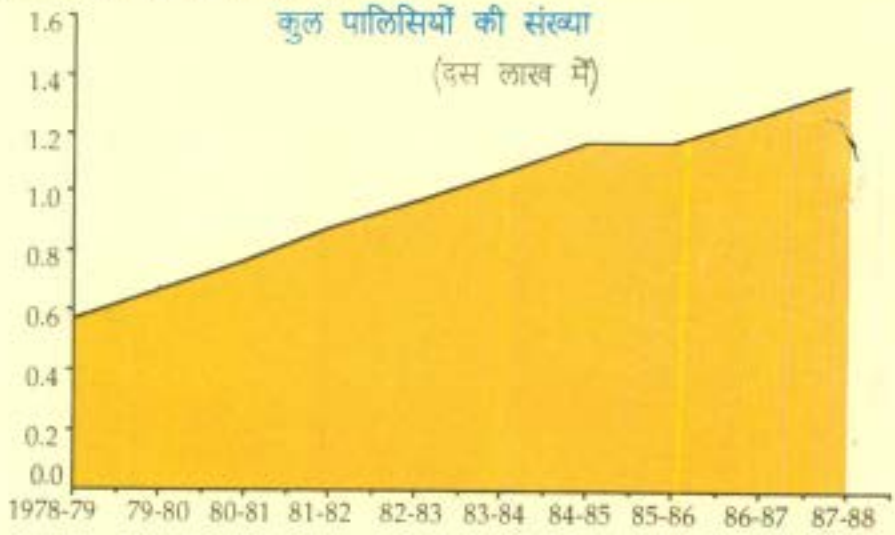

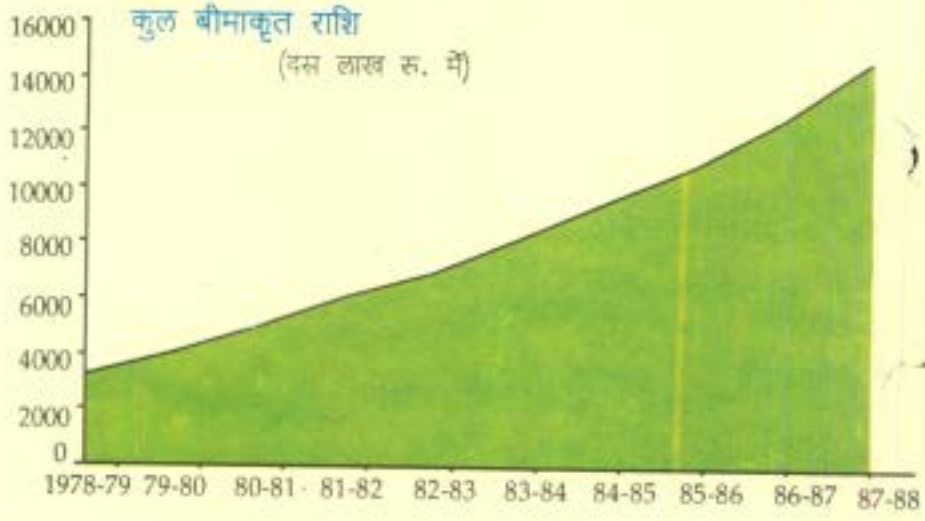

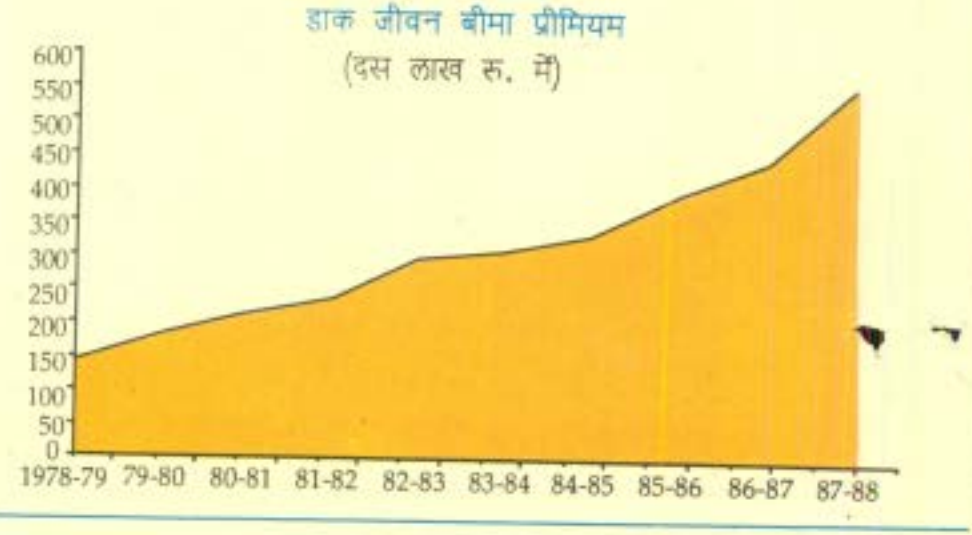

फिलैटली

फिलैटली के क्षेत्र में, नई दिल्ली में 20-29 जनवरी, 1989 तक भारत-89 विश्व फिलैटली प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए तैयारियां प्रारंभ की गई। प्रदर्शनी के स्मरणोत्सव पर जून, 1987 में दो विशेष डाक टिकट जारी किये गये जिनमें प्रदर्शनी के प्रतीक चिह्न और प्रदर्शनी स्थल को चित्रित किया गया था। अक्तूबर, 1987 में चार और डाक-टिकट भी जारी किये गये थे। प्रदर्शनी के स्मरणोत्सव पर दो मिनिएचर शीट भी निकाली गई थीं। इन छः डाक टिकटों सहित, वर्ष के दौरान 62 स्मारक/विशेष डाक-

टिकट जारी किये गये । फिलैटली को बढ़ावा देने और इसके संवर्धन के उद्देश्य से उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान में तीन राज्य स्तर प्रदर्शनियां आयोजित की गई । विभाग ने 'कैपक्स' (कनाडियन फिलैटली प्रदर्शनी), 'हैफिनिया' (द डैनिश फिलैटली प्रदर्शनी) और 'थाईपैक्स' (थाईलैंड फिलैटली प्रदर्शनी) नामक तीन अन्तर्राष्ट्रीय फिलैटली प्रदर्शनियों में भी भाग लिया । देश में 45 फिलैटली ब्यूरो और 142 फिलैटली काउंटरों के माध्यम से काफी संख्या में विशेष विरूपणों के साथ-साथ विशेष आवरण भी जारी किये गये ।

जन शिकायतें

परियात में विलम्ब के संबंध में शिकायतों की संख्या 1986–87 में 7,76,210 से घटकर 1987–88 में 7,11,925 हो गई । कुल परियात की तुलना में निपटाई गई शिकायतों की संख्या 0.00525 प्रतिशत रही । यद्यपि प्रतिशतता की दृष्टि से शिकायतों की संख्या नगण्य है और विभाग के लिए यह सन्तोष की बात है, परन्तु यह मानकर कि किसी भी शिकायत से समूची सेवा की प्रतिष्ठा कम होती है, प्रत्येक शिकायत को दूर करने के लिए सचेतन प्रयास किए जाते हैं तथा यह प्रयास किया जाता है कि उसमें आने वाले अवरोधों को दूर किया जाए । विभाग लगातार होने वाली शिकायतों की मानीटरिंग के लिए जन शिकायत एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के साथ मिलकर कार्य करता रहा है ।

डाक प्रक्रियाओं का सुधार

प्रचालन प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करने के लिए भी प्रयत्न किये गये । मौजूदा प्रक्रियाओं में स्पष्टता लाने और राजस्व की हानि से बचने की दृष्टि से, वस्तुओं की कुछ श्रेणियों जैसे, वाणिज्यिक वस्तुओं जिनमें हस्तलिखित, मोहर लगी, टाइप की हुई, ब्राडमा मुद्रित या कम्प्यूटर मुद्रित प्रविष्टियों को 'बुक पोस्ट' परिभाषा में से निकाल दिया गया है ।

प्रारंभ से ही, डाकघरों में प्राप्त अदत्त तथा कम प्रभार अदा की गई वस्तुओं को इसकी नकदी शेष के एक भाग के रूप में माना जाता था क्योंकि विगत में ऐसे परियात की मात्रा बहुत अधिक थी । बहुत ही कम अदत्त डाक प्रभार की राशि को एक डाकघर के भारी नकदी शेष में शामिल करने की पद्धति की उपयोगिता समाप्त हो गई है । इस पद्धति को अब बदल दिया गया है तथा वास्तव में एकत्रित राजस्व को ही प्राप्तियों के बतौर गिना जाता है, जिससे विभिन्न स्तरों पर लेखा रिकार्डों को रखना सरल हो गया है ।

मानव संसाधन

कर्मचारियों की नियुक्ति

समूचे देश के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे इस व्यापक नेटवर्क के होते हुए विभाग को अपने स्टाफ की दक्षता, परिश्रम और ईमानदारी पर भरोसा करना पड़ता है । विभाग रोज़गार प्रदान करने वाले बड़े सरकारी विभागों में से एक है जिसमें केन्द्रीय सरकार के लगभग 8.93% (31.3.86 की स्थिति के अनुसार) कर्मचारी हैं । 31.3.88 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या 5,89,798 है जिनमें 291 हज़ार नियमित कर्मचारी तथा 298 हजार अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी हैं ।

1978-79 से विभागीय कर्मचारियों की संख्या

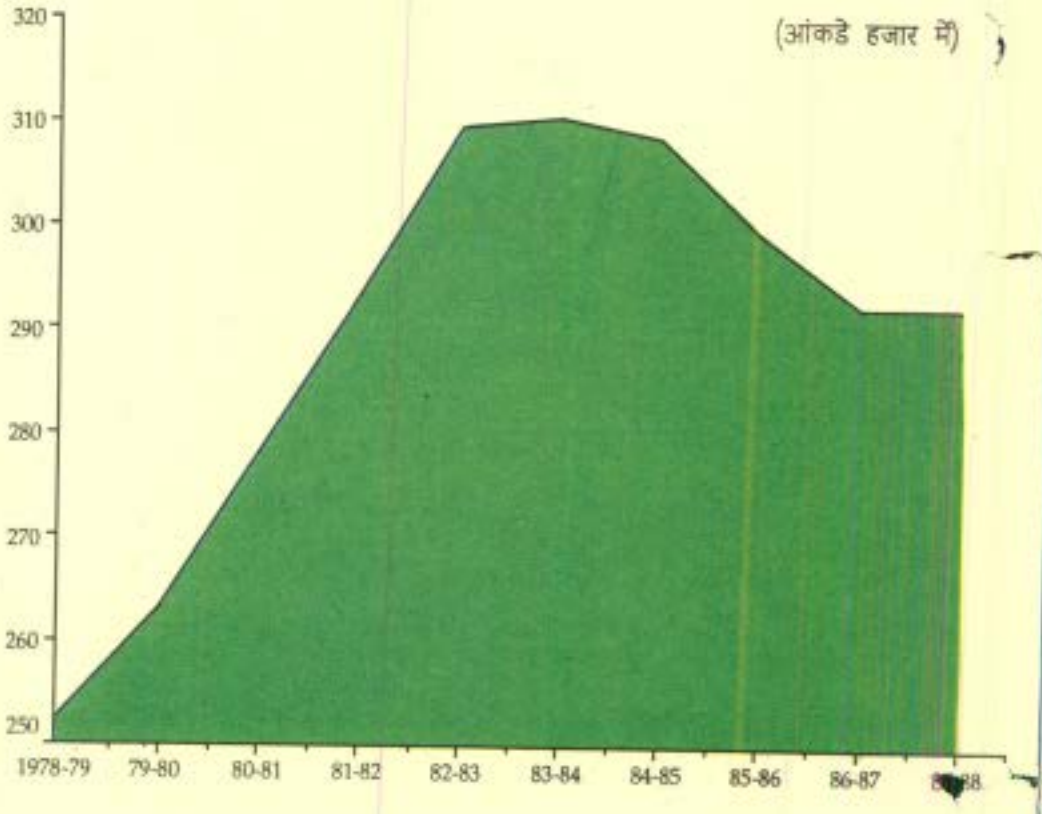

कर्मचारियों की परिलब्धियां

इतनी बड़ी तादाद में कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग ने कल्याण के अनेक नए कदम उठाए हैं । चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, विभाग के सभी कर्मचारियों के वेतन में सामान्य वृद्धि हुई थी ।

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की परिलब्धियों में भी वृद्धि हुई है । महंगाई भत्ते के मामले में उन्हें नियमित विभागीय कर्मचारियों के बराबर ही भत्ता दिया जाता है तथा जब जब भी नियमित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की स्वीकृति दी जाती है तो उन्हें भी इस भत्ते की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

31.3.1988 को कर्मचारियों की संख्या

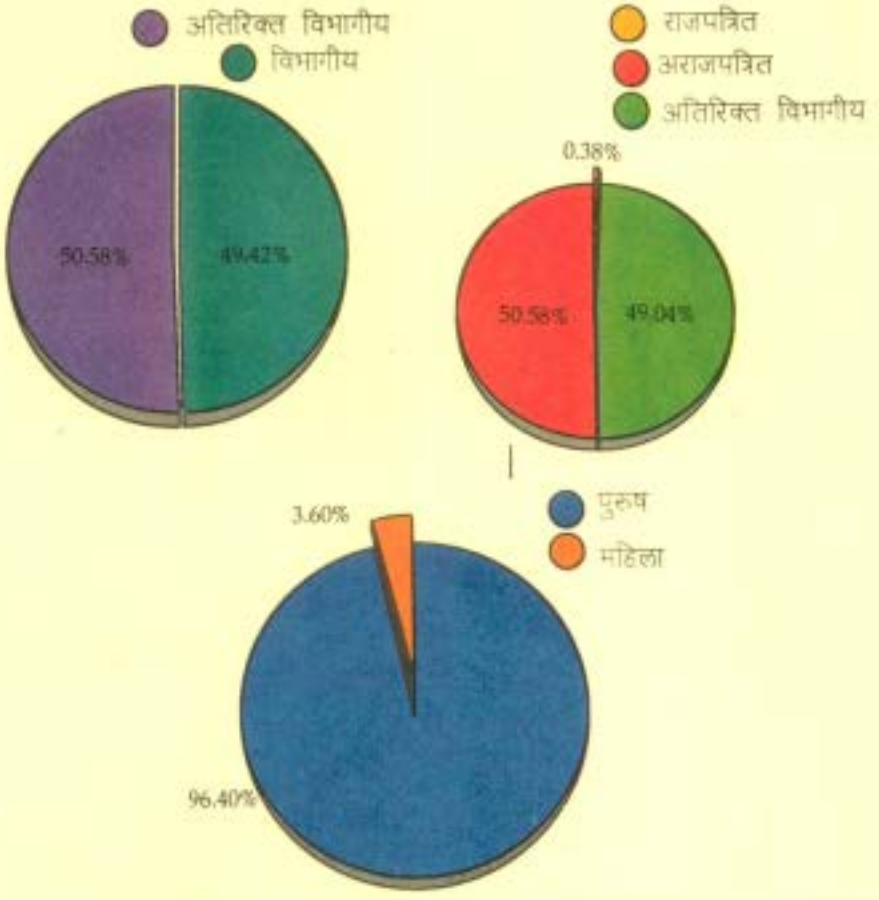

	मूल भत्ते 1.1.1986		संशोधित मूल भत्ते	
	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
अतिरिक्त विभागीय उप पोस्टमास्टर	310	373	385	620
अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर	217	265	275	440
अन्य अतिरिक्त विभागीय एजेंट, अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट, अतिरिक्त विभागीय डाक वाहक (आदि)				
2 घंटे से कम के लिए	191	(नियत)	240	(नियत)
2 घंटे और अधिक के लिए	214	254	270	420

अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को अदा किये जा रहे अन्य भत्तों को भी निम्नानुसार संशोधित कर दिया गया है:

भत्ते का नाम	मौजूदा दर	संशोधित दर
	रु.	रु.
अतिरिक्त विभागीय पोस्टमास्टरों को वितरण तथा सवारी भत्ता	15/-	50/-
साइकिल भत्ता	8/-	20/-
कार्यालय रख-रखाव भत्ता	10/-	25/-
अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को नियम लेखन सामग्री प्रभार	1/-	3/-

प्रशिक्षण

स्टाफ को प्रशिक्षण दिलाना विभाग का एक मुख्य कार्य रहा है। इस समय पांच क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं, जो प्रचालन और पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों को प्रारंभिक और सेवाकालीन प्रशिक्षण देते हैं। वर्ष के दौरान लगभग 7000 कर्मचारियों को यह प्रशिक्षण दिया गया। विभाग के राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों, पोस्टल स्टाफ कालेज द्वारा भारतीय डाक सेवा और भारतीय डाक-तार वित्त एवम् लेखा सेवा के सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है। विभिन्न कैडरों के 130 अधिकारियों ने पोस्टल स्टाफ कालेज द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया जिसमें पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला और प्रशासकीय विकास कार्यक्रम भी शामिल हैं।

प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा दूसरे देशों के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। पोस्टल स्टाफ कालेज द्वारा सार्क देशों के 11 अधिकारियों के लिए भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इथोपिया, सीरिया, लियोन, सूरीनाम, यूगांडा, यमन और लाइबेरिया के मध्यम वर्ग के अधिकारियों के लिए आधुनिक प्रबंध विषय पर डाक प्रशिक्षण केन्द्र मैसूर में एक पाठ्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र में सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और विभिन्न कैडरों की सामग्री की व्यापक समीक्षा की जाती है। उन्होंने सभी कैडरों के 10,000 डाक कर्मचारियों और 5,000 से अधिक उपभोक्ताओं के लिए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण भी किया है। इन सर्वेक्षणों से प्राप्त जानकारी को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को फिर से तैयार करने के लिए प्रयोग में लाया गया।

कर्मचारी संबंध

डाक विभाग ने तीन फेडरेशनों सहित 29 यूनियनों /एसोसिएशनों को डाक कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मान्यता प्रदान की है। अप्रैल, 1987 से मार्च, 1988 तक की अवधि के दौरान तीन फेडरेशनों द्वारा 13 सूत्री मांगों के समर्थन में 14.7.1987 से 20.7.87 तक हड़ताल का संयुक्त नोटिस दिये जाने के कारण यूनियन तथा प्रशासन के बीच संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न हो गया था। दूसरी यूनियन जो पोस्टमैन तथा वर्ग 'घ' के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, ने भी नवंबर, 1987 में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की मांगों से संबंधित एक हड़ताल का नोटिस दिया था। एक यूनियन ने अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों की कुछ मांगों को पूरा कराने के लिए डाक भवन पर दो बार धरना दिया।

प्रशासन और यूनियन के बीच विभिन्न मुद्दों पर हुए मत-भेदों को आपसी विचार-विमर्श और बैठक के जरिए निपटा लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप हड़ताल के दोनों नोटिस वापिस ले लिये गये और धरना भी समाप्त कर दिया गया। इस अवधि के दौरान घटने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना एक कार्यालय ज्ञापन के निपटान की थी जिस पर सचिव (डाक) ने 11.7.1987 को तीन फेडरेशन के साथ हस्ताक्षर किये गये जिसमें अनेक ऐसी मदें थीं जिनके लिए डाक विभाग के कर्मचारी आन्दोलन कर रहे थे। इसके निपटान के बाद विभाग में सभी स्थानों पर औद्योगिक सामंजस्य स्थापित कर दिया गया।

विभागीय परिषद (जे सी एम) की बैठक 7 और 8 सितम्बर, 1987 तथा 28 और 29 जनवरी, 1988 को हुई। सितम्बर, 1987 में आयोजित विभागीय परिषद की बैठक में 51 मदों पर और बाद में जनवरी, 1988 में आयोजित विभागीय परिषद की बैठक में 67 मदों पर विचार किया गया। इसके अतिरिक्त फेडरेशनों तथा गैर फेडरेशनों /यूनियनों /एसोसिएशनों के साथ बहुत सी आवधिक बैठकें भी की गई जिनमें कर्मचारियों की लंबित मांगों को निपटाया गया।

राष्ट्रीय डाक पुरस्कार

कर्मचारियों की सराहनीय सेवाओं को मान्यता देना और उन्हें सम्मानित करना एक महत्वपूर्ण प्रेरणादायक कदम है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 1984 से राष्ट्रीय डाक पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया। इन पुरस्कारों को 'मेघदूत' पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। पुरस्कार सर्किल स्तर पर भी दिये जाते हैं जिन्हें 'डाक सेवा' पुरस्कार के नाम से जाना जाता है।

निम्नलिखित श्रेणियों के उन कर्मचारियों को पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्हें सर्किल अध्यक्षों की सिफारिशों के आधार पर चुना जाता है।

- सभी श्रेणियों के अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी
- वर्ग 'घ' कर्मचारी, पोस्टमैन या समकक्ष पद
- डाकघर, डाक कार्यालय आदि जैसे किसी कार्यालय के प्रधान की हैसियत से कार्य करने वाले ग्रुप 'ग' कर्मचारी।
- डाक और छंटाई सहायक
- सभी श्रेणियों के अवर या उच्च चयन ग्रेड के पर्यवेक्षण कर्मचारी, निरीक्षक और सहायक अधीक्षक।
- उपर्युक्त किसी भी श्रेणी से संबंधित महिला कर्मचारी।

डाक विभाग के निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष 1986-87 के 'मेघदूत' पुरस्कार तत्कालीन संचार मंत्री श्री अर्जुन सिंह द्वारा 9 अक्तूबर, 1987 को सलेम (तमिलनाडु) में विश्व डाक दिवस के उपलक्ष पर दिये गये।

- श्री जोगा राम, अतिरिक्त विभागीय रनर (हिमाचल प्रदेश)
- श्री पी. गिरिराजन, पोस्टमैन, मद्रास
- श्री एन. दिवाकरन, कार्यालय सहायक एर्णाकुलम (केरल)
- श्री राम चन्द पंडा, अवर चयन ग्रेड, उप पोस्टमास्टर, कटक (उड़ीसा)

● श्री एम. वी. पेंडसे, अवर चयन ग्रेड, सुपर-वाइजर, विदेश डाक बंबई

● श्रीमती दर्शन देवी अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर, श्री गंगा नगर (राजस्थान)

चिकित्सा सुविधाएं

कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की देख-रेख के लिए डाक विभाग देश के 45 स्थानों पर 54 औषधालय चला रहा है जो घर जाकर मरीज को देखने, नैमित्तिक प्रयोगशाला जांच और दवाई की सप्लाई सहित बहिरंग चिकित्सा सुविधा प्रदान करते हैं। ये औषधालय दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों को भी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते हैं। औषधालय कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों को समय से तथा पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते हैं।

कल्याण

डाक विभाग जैसे संगठन के लिए, जिसमें कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक है, कर्मचारी कल्याण का अत्यंत महत्व है। इस बात को ध्यान में रखते हुए संचार मंत्री की अध्यक्षता में एक 'डाक सेवा कर्मचारी कल्याण बोर्ड' का गठन किया गया है। इस बोर्ड का उद्देश्य विभाग में कर्मचारियों के लिए सुख-सुविधाओं को बढ़ाना और कल्याण कार्यक्रमों, खेलों एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास करना है। वर्ष के दौरान बीमारी/मृत्यु, शैक्षिक छात्रवृत्ति, खेलों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा मनोरंजन क्लबों आदि को आर्थिक सहायता के रूप में 66 लाख रुपये दिए गए।

कर्मचारियों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की दरों तथा बीमारी के कारण लम्बी छुट्टी पर जाने वाले कर्मचारियों को आर्थिक सहायता और छयरोग के मरीजों को दी जाने वाली अनुदान राशि में भी वृद्धि की गई। छात्रवृत्ति देने की पात्रता की सीमा में भी संशोधन किया गया। कर्मचारियों को विश्राम तथा मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करने के लिए 16 शहरों में हॉली-डे होम स्थापित किये गये हैं।

वर्ष के दौरान 15 विभिन्न खेलों में मंडलीय, क्षेत्रीय, और अखिल भारतीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विभागीय खिलाड़ियों ने वालीबाल, कुश्ती, शतरंज, वेटलिफ्टिंग, टेबल टेनिस, कबड्डी और एथलेटिक्स जैसी 11 खेल प्रतियोगिताओं की राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में भाग लिया। बिहार सर्किल के एक शतरंज खिलाड़ी ने अक्तूबर, 1987 में लायड्स बैंक मास्टर शतरंज चैम्पियनशिप में भाग लिया। बेंगलुर में एक अखिल भारतीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें डाक विभाग के कर्मचारियों के बच्चों तथा परिवार के सदस्यों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति

विभाग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के आवेदकों की भर्ती के रियायती मानदंड अपनाने के प्रयोजन से विशेषतया विभागीय अर्हक परीक्षा में, मौजूदा सरकारी आदेशों को पूरी तरह कार्यान्वित कर रहा है।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को पर्याप्त प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने यह निर्णय और लिया है कि यदि रियायती मानदंडों के अंतर्गत भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के आवेदक अपेक्षित संख्या में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं तो अनुत्तीर्ण आवेदकों के मामलों की उनकी सेवा के गोपनीय रिकार्ड तथा परीक्षा में किए गए प्रदर्शन के आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए। यह समीक्षा मुख्यतः उच्च दायित्व के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की समिति द्वारा की जाती है।

जिन उम्मीदवारों को पदोन्नति के अयोग्य नहीं पाया जाता, उन्हें अर्हता स्तर तक लाने के लिए, जहां अपेक्षित होता है, अनुग्रह अंक दिए जाते हैं। इस प्रकार विभाग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के प्रयोजन से, मौजूदा आदेशों की भावना को देखते हुए विशेष प्रयास किए हैं।

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के 15-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। विभाग की भर्ती यूनिटें तिमाही विवरण सीधे कल्याण विभाग के अल्पसंख्यक सैल को प्रस्तुत कर रही हैं, जिनमें प्रत्येक तिमाही के दौरान भर्ती किए गए विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों का प्रतिशत अंकित होता है। जो संबंधित अधिकारी इस काम पर नजर रख रहे हैं, उन्होंने विभाग के कार्य को संतोषजनक पाया है।

कार्य अध्ययन और अध्ययन पद्धति

विभाग में एक आंतरिक कार्य अध्ययन यूनिट है जो फील्ड यूनिटों में कर्मचारियों के निर्धारण संबंधी मानदंडों से जुड़े विश्लेषण-अध्ययन तथा कार्य को आंकने और अध्ययन पद्धति संबंधी कार्य करती है। वर्ष के दौरान, निम्नलिखित अध्ययन कार्य पूरे किए गए:

- प्रधान डाकघरों के सृजन से संबंधित मानदंडों का संशोधन।
- मुख्य (मेन) डाकघरों और अन्यथा निर्धारित डाकघरों (सेकिन्ड आफिस ऑव पोस्टिंग) में फ्रैंकिंग मशीनों पर कार्य करने वाले ग्रुप 'ग' कर्मचारियों और सहायक कर्मचारियों से संबंधित मानदण्डों का मूल्यांकन।
- डाकघरों में इन्दिरा विकास पत्रों की बिक्री से जुड़े ग्रुप 'ग' कर्मचारियों की मंजूरी से संबंधित

मानदंडों का मूल्यांकन ।

- केरल खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के उपबंधों के अधीन पेंशन का भुगतान करने के काम से जुड़े ग्रुप 'ग' कर्मचारियों से संबंधित मानदंडों का मूल्यांकन ।
- विदेश डाकघर की प्रशासनिक शाखा के ग्रुप 'ग' कर्मचारियों से संबंधित मानदंडों का मूल्यांकन ।
- डाक परियात का नमूना सर्वेक्षण ।
- डाक निदेशालय के पी. एम. आर., पी. आर. पी., सतर्कता- III, यू. पी. ई. नकदी एवं लेखा / वेतन बिल अनुभाग और बचत बैंक अनुभागों का अध्ययन ।
- डाक निदेशालय के पीई- I और पीई- II अनुभागों की कार्य-पद्धति का अध्ययन ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिशत
(1987-88)

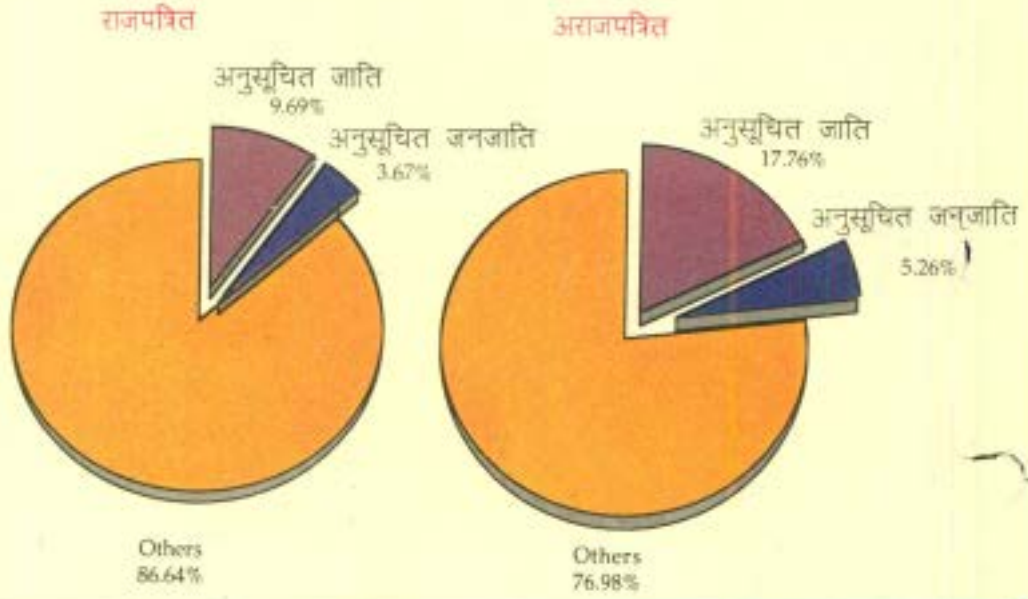

सरकारी काम-काज में हिन्दी का प्रयोग

विभाग के सरकारी काम-काज में हिन्दी का राजभाषा के रूप में उत्तरोत्तर प्रयोग किया जा रहा है । सरकारी काम-काज में हिन्दी का अधिक-से-अधिक प्रयोग करने के लिए प्रभावशाली कार्रवाई की गई है । राजभाषा अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष के दौरान चार बैठकें हुईं । संचार मंत्रालय हिन्दी सलाहकार समिति, संचार मंत्री की अध्यक्षता में, विभाग में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए निरंतर मार्गदर्शन और सुझाव देती रही । हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत पैंतीस अधिकारियों को हिन्दी प्रशिक्षण के लिए भेजा गया । डाक निदेशालय में कार्य कर रहे टाइपिस्टों और स्टेनोग्राफरों को हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी स्टेनोग्राफी में प्रशिक्षण देने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम शुरू किया गया है और इसके अनुसार कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है । नोटिंग और ड्राफ्टिंग हिन्दी में करने में कर्मचारियों की झिझक दूर करने के प्रयोजन से निदेशालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए तीन कार्यशालाएं आयोजित की गईं । वर्ष के दौरान, ऐसे 54 कार्यालयों को राजपत्र में अधिसूचित किया गया जिनके 80 प्रतिशत या इससे अधिक कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान था । ग्यारह विभागीय नियम पुस्तक डिग्लॉट रूप में छापी गई और आठ छप रही हैं । पठनीय हिन्दी पुस्तकों की एक विस्तृत सूची तैयार की गई और सर्किलों को उन्हें अपने-अपने पुस्तकालयों के लिए खरीदने की सिफारिश की गई ।

निदेशालय में 7.12.87 से 11.12.87 तक और अधीनस्थ कार्यालयों में 14.9.87 से 18.9.87 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया । सप्ताह के दौरान अपना-अपना सरकारी काम-काज हिन्दी में करने के लिए कर्मचारियों को पुरस्कार दिए गए । 27.8.87 व 28.8.87 को एक अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें हिन्दी को बढ़ावा देने और सरकारी काम-काज में उसका प्रयोग बढ़ाने से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श किया गया । संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति ने इस वर्ष के दौरान विभाग के अनेक अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया और साथ ही 23.12.87 को निदेशालय का भी निरीक्षण किया । समिति द्वारा बताई गई कमियों की जांच की गई और उन्हें दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं ।

डाक वित्त

1960–61 से डाक सेवाएं, जो पहले सामान्य राजकोष पर भार डाले बिना राजस्व और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखने में सक्षम थी, धीरे-धीरे घाटे की ओर बढ़ रही हैं । जबकि डाक सेवाओं की प्रचालन लागत निरंतर बढ़ती रही, विभिन्न डाक सेवाओं की दरें या तो वही बनी रहीं या उनमें केवल नाम-मात्र की वृद्धि की गई, किन्तु यह वृद्धि भी उन पर आने वाली आर्थिक लागत से काफी कम रखी गई थी । परिणामस्वरूप इन पर होने वाले घाटे को, सामान्य राजकोष पर भार डाले बिना, दूरसंचार सेवाओं द्वारा पूरा किया जाता था । 1.1.1985 से डाक और तार विभाग का विभाजन होने से, डाक सेवाओं को, विभाग के भीतर ही दूरसंचार सेवाओं की अतिरिक्त आय से मिलने वाली आर्थिक सहायता की संभावना समाप्त हो गई । डाक सेवाओं के प्रचालन में होने वाला घाटा अब सामान्य राजकोष पर एक भार बन गया है ।

एक अलग विभाग के रूप में कार्य करते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान विभाग को वर्ष 1985–86, 1986–87 और 1987–88 में क्रमशः 163.55 करोड़ रु., 216.43 करोड़ रु. और 190.87 करोड़ रु. के राजस्व का घाटा हुआ ।

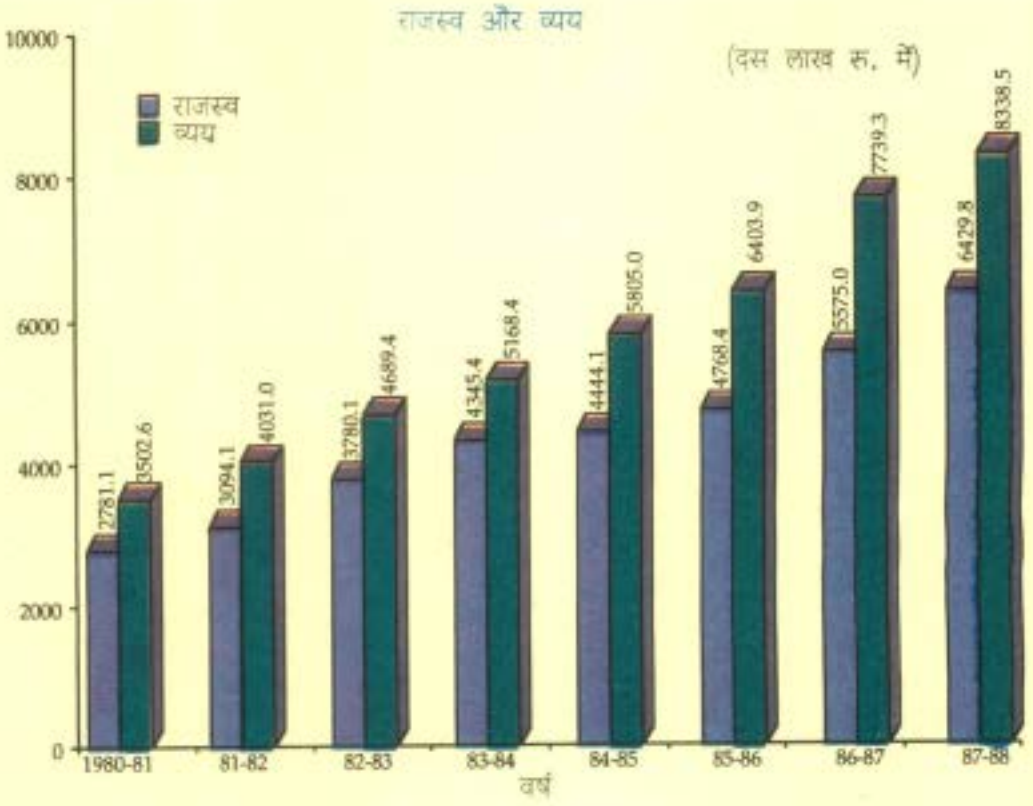

1.1.1987 से अनेक डाक सेवाओं के मूल्यों में संशोधन करने के बावजूद, विभिन्न सेवाओं की लागत उनके द्वारा अर्जित किए जाने वाले राजस्व की तुलना में निरंतर बढ़ती रही । लगभग सभी सेवाओं के मामले में राजस्व उन पर आने वाली सीधी लागत से काफी कम था । सामान्य प्रशासन, लेखा, भंडारण और वितरण आदि की ऊपरी लागत को यदि सभी प्रकार की डाक सेवाओं में बांटा जाता, तब भी उनकी लागत उनके द्वारा अर्जित राजस्व की तुलना में अधिक होगी ।

सेवा का नाम	सीधी यूनिट लागत पैसों में	औसत राजस्व घाटा पैसों में	प्रति यूनिट पैसों में	लाभ कुल लागत करोड़ रु. में
पोस्टकार्ड	70.09	20.50	49.59	– 466.1
पत्र कार्ड	78.75	35.00	43.75	– 393.8
पत्र	92.66	100.00	+ 7.34	+ 94.7
रजिस्टर्ड				
समाचारपत्र				
एक	127.59	21.00	106.59	– 234.5
पुलिंदा (बंडल)	184.25	46.00	138.25	– 55.3
बुक पैकेट				
बुक पैटर्न और सेंपल पैकेट	137.57	81.00	56.57	– 124.5
मुद्रित पुस्तकें	193.59	81.00	112.59	– 56.3
अन्य पत्रिकाएं	220.69	100.00	120.69	– 70.00
रिकार्डिड डिलीवरी	311.32	207.00	104.32	– 07.1
पार्सल	957.43	903.00	54.43	– 32.7
रजिस्ट्रेशन	654.45	320.00	334.45	– 769.2
मूल्यदेय	831.41	260.00	571.41	– 45.7
बीमा	1424.98	770.00	654.98	– 59.7
पावतियां	63.63	74.00	+ 10.37	+ 18.1
मनीआर्डर	629.73	650.00	+ 20.27	+ 24.4
तार मनीआर्डर	830.00	285.00	545.00	– 14.7
इंडियन पोस्टल आर्डर	360.54	60.00	300.54	– 70.0
				– 2262.4
उपरि खर्चे				
प्रशासन				698.0
लेखा				201.4
लेखा-परीक्षा				16.7
भंडारण एवं वितरण				37.0
				– 3215.5

वर्ष 1987–88 के दौरान अर्जित कुल राजस्व 642.98 करोड़ रु. था, जो 1986–87 के दौरान अर्जित राजस्व की तुलना में कुल 85.48 मिलियन रु. और प्रतिशत में 15.3 प्रतिशत अधिक था । वर्ष में जितना राजस्व अर्जित करने का अनुमान किया गया था, उसमें से 98.2 प्रतिशत राजस्व वसूल किया गया ।

	राशि (मिलियन रु. में)	प्रतिशत
— डाक टिकटों की बिक्री	3812.1	59.3
— नकद वसूल किया गया डाक शुल्क	1129.3	17.6
— मनीआर्डरों और इंडियन पोस्टल आर्डरों पर कमीशन	799.6	12.4
— अन्य प्राप्तियां	688.8	10.7

वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के लिए चुनिन्दा डाक वस्तुओं पर औसत लागत और औसत राजस्व (पैसों में)

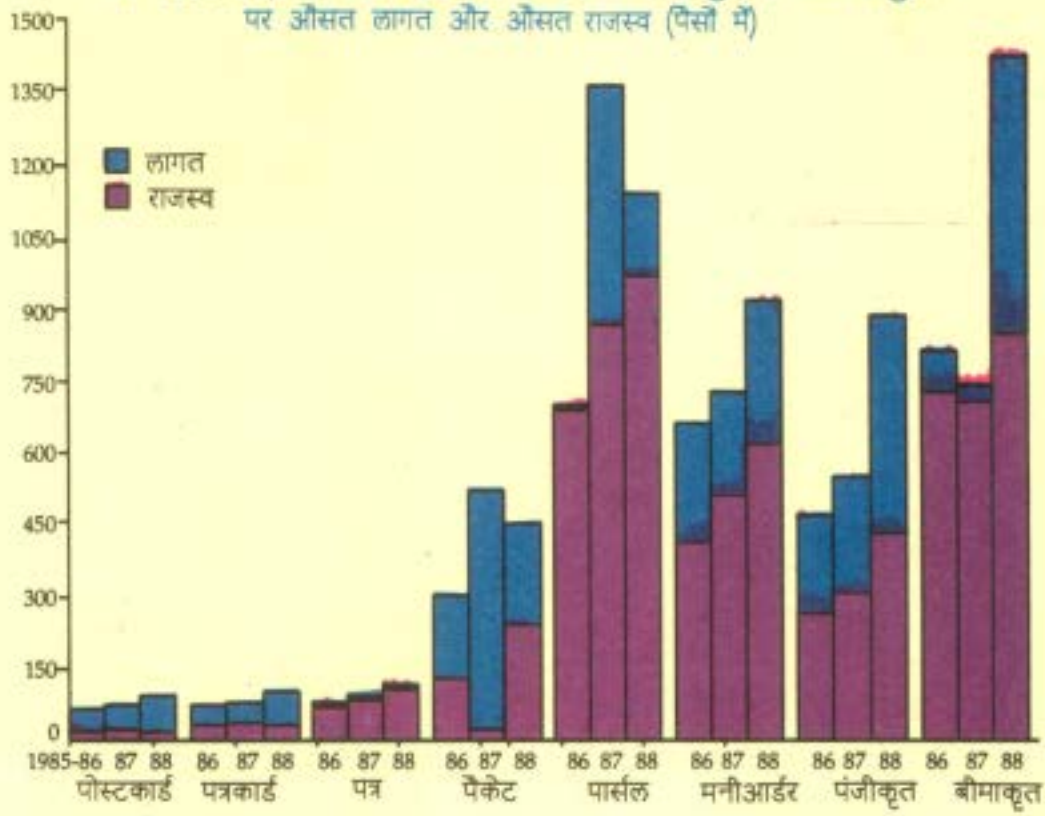

वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के लिए चुनिन्दा डाक वस्तुओं का राजस्व और व्यय

(राशि दस लाख रु. में)

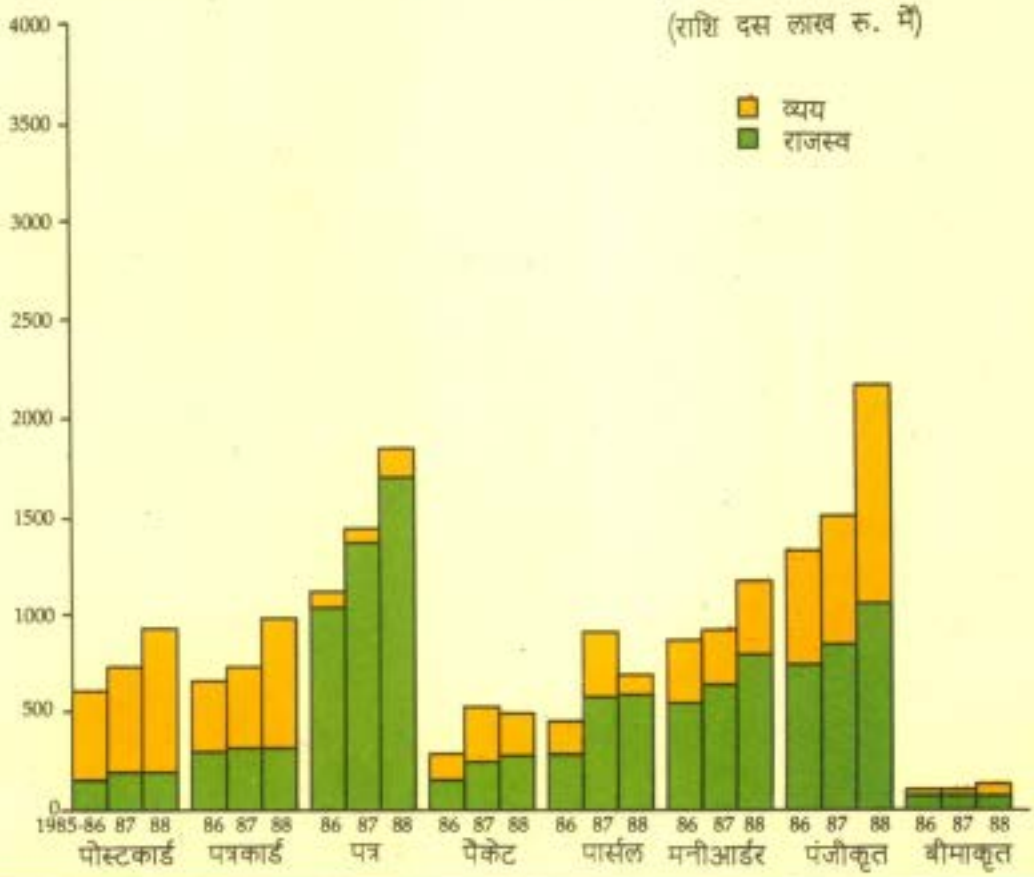

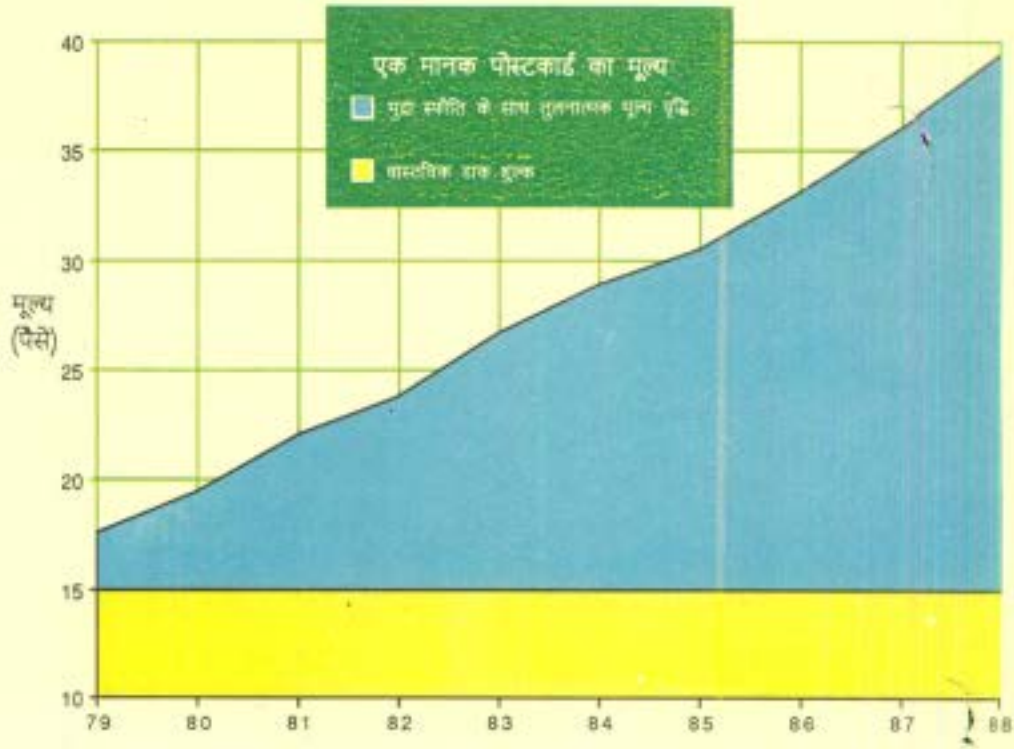
एक मानक पोस्टकार्ड का मूल्य
मुद्रा स्फीति के साथ तुलनात्मक मूल्य वृद्धि
वास्तविक डाक शुल्क
मूल्य (पैसे)
40
35
30
25
20
15
10
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

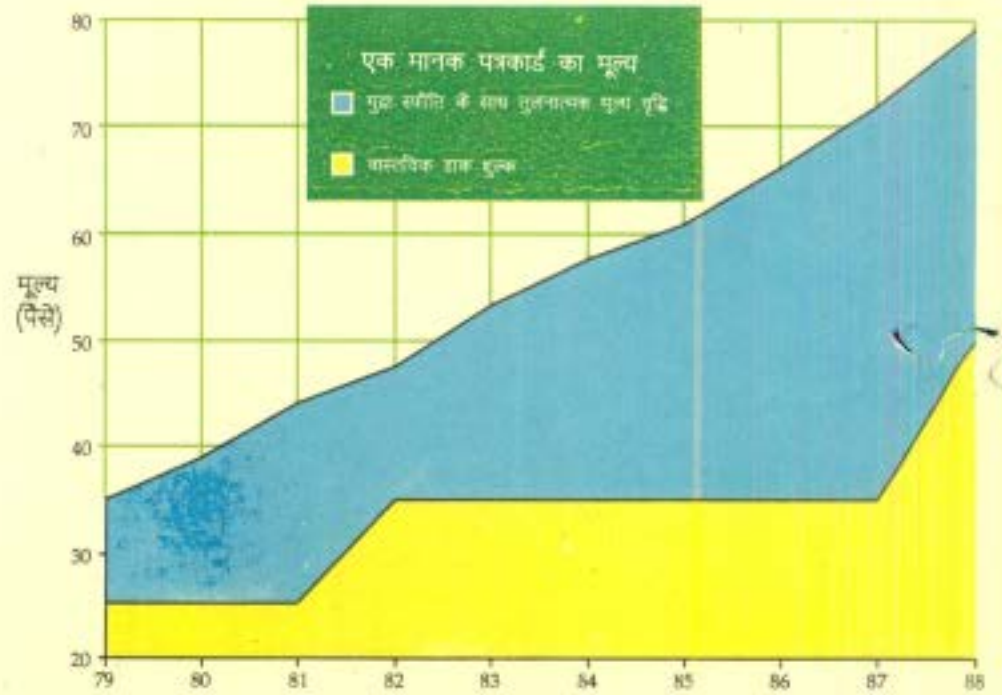
एक मानक पत्रकार्ड का मूल्य
मुद्रा स्फीति के साथ तुलनात्मक मूल्य वृद्धि
वास्तविक डाक शुल्क
मूल्य (पैसे)
80
70
60
50
40
30
20
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

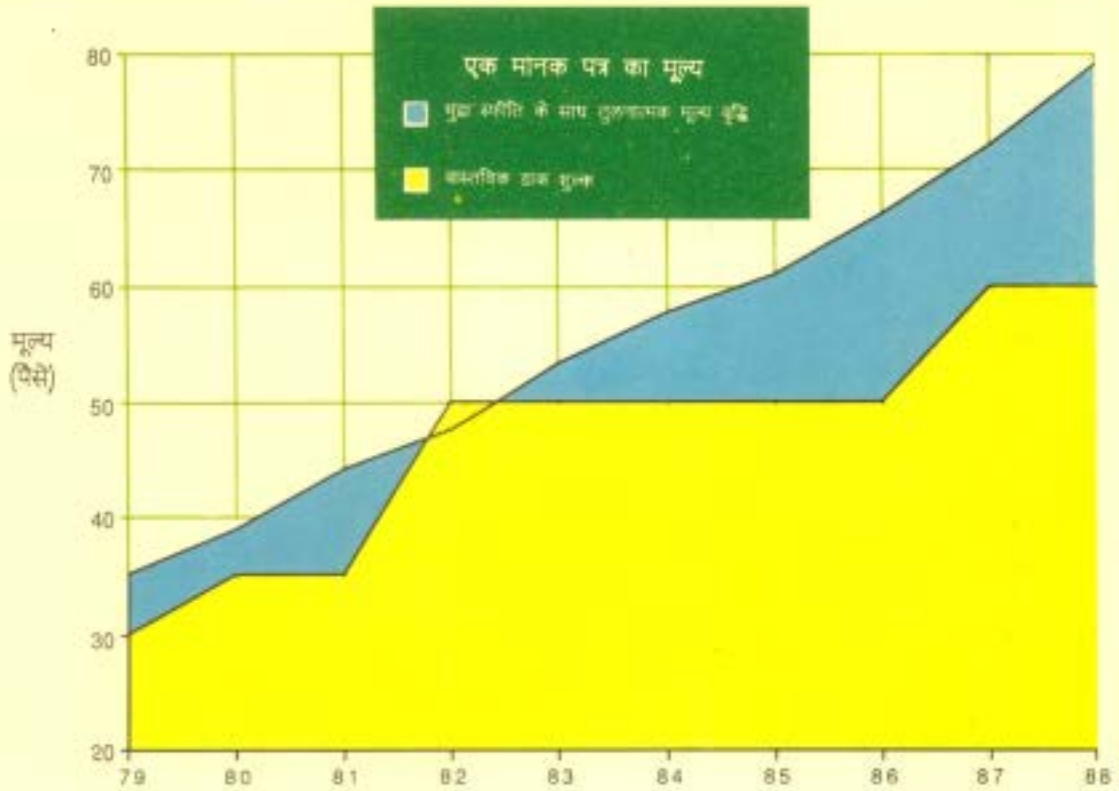

वर्ष 1987–88 के दौरान नेट कार्यकारी खर्च 789.62 करोड़ रु. के अनुमानित खर्च की तुलना में 833.85 करोड़ रु. था, जो 44.23 करोड़ रु. अधिक था। यह वृद्धि, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप न्यूनतम वेतन में वृद्धि तथा न्यूनतम पेंशन और परिवार पेंशन में संशोधन के कारण हुई। महत्वपूर्ण श्रेणियों के अंतर्गत खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है:

	राशि (करोड़ रु. में)	प्रतिशत
— सामान्य प्रशासन	686.7	8.24
— प्रचालन	5651.5	67.85
— एजेंसी सेवाएं	258.5	3.10
— अन्य	1736.0	20.81

महत्वपूर्ण श्रेणियों का कुल राजस्व खर्च नीचे दिया गया है:

	राशि (मिलियन रु. में)	कुल खर्च का प्रतिशत
— वेतन और भत्ते, आकस्मिक व्यय, अंतरिम सहायता और अन्य मदें:	830.58	80.85
— लेखा और लेखा-परीक्षा	23.10	2.25
— पेंशन प्रभार	96.34	9.38
— डाक टिकट, पोस्टकार्ड	20.78	2.02
— स्टेशनरी और मुद्रण आदि	88.2	0.86
— परिसम्पत्तियों आदि का रखरखाव	51.9	0.51
— छोटे-मोटे कार्य	12.4	0.12
— डाक लाना-ले-जाना (रेल विभाग और एयर मेल कैरियर्स को भुगतान)	411.9	4.01

वर्ष 1987-88 के लिए राजस्व और व्यय

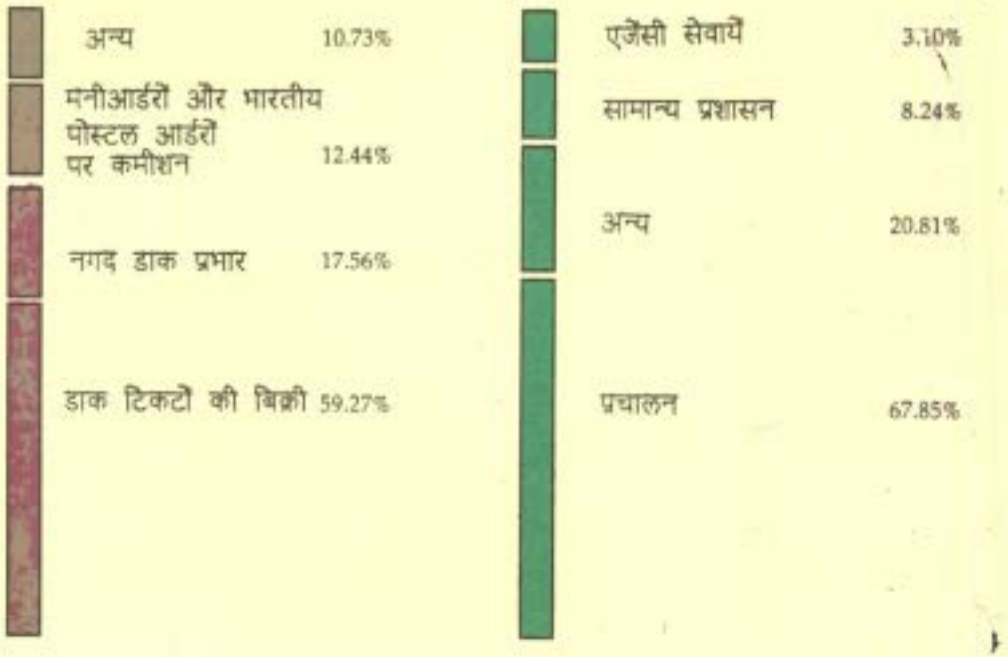

पूंजीगत परिव्यय

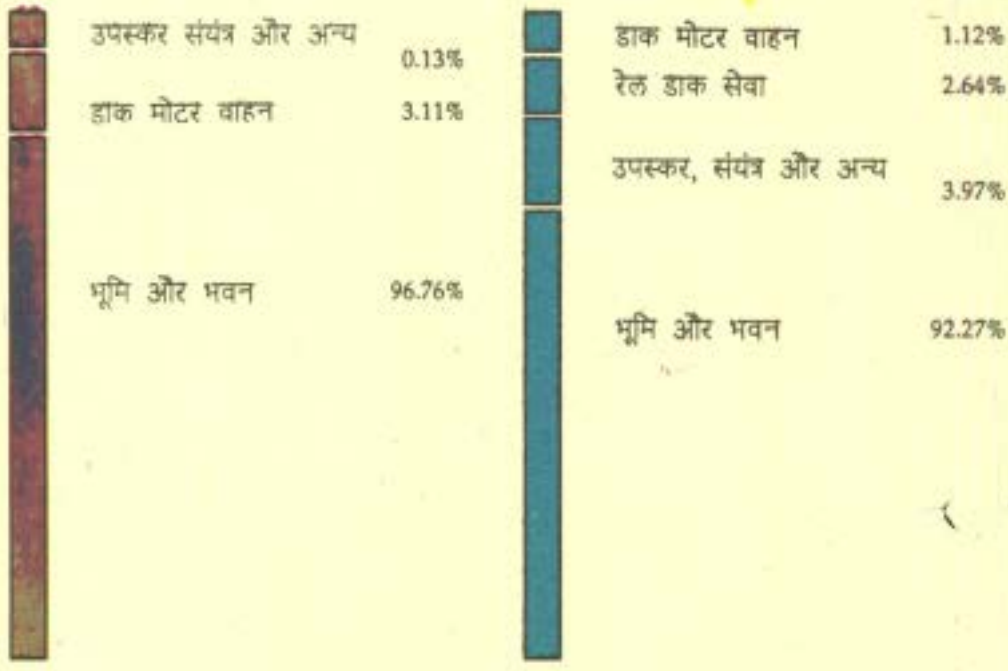

1987-88 का घाटा 1908.7 मिलियन रु. था जो वर्ष 1986-87 (2164.3 मिलियन रु.) के घाटे से 255.6 मिलियन कम था।

वर्ष के दौरान अचल सम्पत्तियों पर कुल परिव्यय 305.2 मिलियन रु. था। (96.76 प्रतिशत भूमि और भवनों पर तथा 3.24 प्रतिशत उपकरणों, संयंत्रों तथा अन्य पर)। वर्ष के अंत में अचल परिसम्पत्तियों का पूंजीगत परिव्यय 3266.8 मिलियन रुपयों तक पहुंच गया। वर्ष के अंत में सामान्य राजस्व से वित्तीय संसाधनों प्राप्ते अगला क्रमिक पूंजीगत परिव्यय 2644.6 मिलियन रु. था।

कार्य प्रगति (1.4.1988 से 31.12.1988)

डाक नेटवर्क का अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों और औद्योगिक परियोजना क्षेत्रों में विस्तार किया जाता रहा। देश के विभिन्न भागों में 60 नए शाखा डाकघर और 23 विभागीय उप-डाकघर खोले गए। आर्थिक शर्तों संबंधी घाटे की अनुमेय सीमा को छोड़ते हुए ग्रामीण डाकघर खोलने की नीति को और अधिक उदार बनाया गया क्योंकि उक्त सीमा सामान्य क्षेत्रों में लागत का 33⅓ प्रतिशत निर्धारित न्यूनतम राजस्व तथा पहाड़ी, जनजातीय और पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत आय अर्जित करने के अनुकूल नहीं थी।

देश के विभिन्न भागों में 3386 डाक सेवकों की नियुक्ति के साथ ही नई पंचायत डाक सेवक योजना को एक ठोस आकार और मजबूती प्रदान की गई। इस योजना के अधीन, जिन ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं में डाकघर नहीं हैं, उन्हें गांव में ही डाक सुविधाएं मुहैया कराने के लिए अपने डाक सेवक रखने के प्रयोजन से 150/- रु. मासिक नकद अनुदान दिया जाता है। इन ग्राम पंचायतों को विभाग द्वारा आवश्यक सेवा अनुबन्ध तथा डाक टिकटों और स्टेशनरी की बिक्री पर काफी कमीशन दिया जाता है।

डाक परेषण प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के प्रयोजन से वर्तमान बेड़े को मजबूत बनाने के लिए तथा छोटे शहरों में डाक वाहनों को आधुनिक बनाने के लिए 55 मेल मोटर वाहन बदले गए। 24 वाहन केवल स्पीड पोस्ट सेवा के लिए ही खरीदे गए।

आधुनिकीकरण पर निरंतर जोर देते हुए, डाक लाने-ले-जाने के लिए प्रयुक्त जूट कैनवास के भारी थैलों को हल्के थैलों द्वारा बदलने के प्रयास किए गए। जूट टैक्नोलॉजीकल लैबोरेट्री के सहयोग से नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग कार्पोरेशन द्वारा विनिर्मित हाई डैन्सिटी पॉलीथीन मैटीरियल का चुने हुए डाकघरों में शीघ्र परीक्षण किया जाने वाला है।

फिलैटली के क्षेत्र में, भारत 89 विश्व फिलैटली प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए अनुकूल तैयारियां की गईं। 9 अक्तूबर, 1988 को विश्व डाक दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी के उपलक्ष्य में दो डाक टिकटों का एक सेट जारी किया गया जिसमें प्राचीन और वर्तमान वास्तुशिल्प के नमूनों के उदाहरण स्वरूप बम्बई और बेंगलूर जी. पी. ओ. के भवनों को दर्शाया गया है। रेल डाक सेवा और पुनः प्रेषण केन्द्र की मोहरों (चिह्नणों) पर दो अन्य डाक-टिकट दिसम्बर, 1988 में जारी किए गए। इनके अलावा, इस अवधि के दौरान 37 और डाक टिकट जारी किए गए। विभाग ने तीन अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों —फिनलैंडिया-88, प्राग-88 और ओलिम्फिलेक्स-88 में भाग लिया। इनके अलावा, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक में दो राज्य स्तरीय प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।

बचत बैंक संगठन ने 1.4.1988 से किसान विकास पत्र की शुरुआत के साथ विकास प्रक्रिया में एक और कदम बढ़ाया। इस बचत पत्र की परिपक्वता अवधि 5½ वर्ष और इस पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत है। मासिक आय योजना में एकल खाते में जमा की अधिकतम सीमा को एक लाख रु. से बढ़ाकर 2 लाख रु. और संयुक्त खाते में 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रु. कर दिया गया। डाकघर के चैकों के निपटान को सुविधाजनक बनाने के लिए, और 230 प्रधान डाकघरों को लोकल क्लियरिंग हाउसेज की पूर्ण इकाई के रूप में शामिल किया गया।

मानव संसाधनों के विकास के लिए एक निवेश के रूप में प्रशिक्षण को निरंतर महत्व दिया जाता रहा। पोस्टल स्टाफ कालेज द्वारा अनेक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए गए जिनमें प्रबंध विकास कार्यक्रम, डाक परेषण पर सेमिनार, डाक आधुनिकीकरण, कार्मिक नीति और संगठनात्मक संरचना और अंतर्राष्ट्रीय डाक परिचालन शामिल है।

1985 से अब तक: उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण

एक जनोपयोगी सेवा

डाक विभाग देश में 12 करोड़ परिवारों को सेवाएं प्रदान करने के लिए संसाधनों के दबाव के बावजूद, अपने नेटवर्क का निरंतर विस्तार करता रहा है। 1.4.1988 को समाप्त पिछले तीन वर्षों की अवधि के दौरान, 898 नए डाकघर खोले गए, जिनको मिलाकर देश में डाकघरों की कुल संख्या 1,44,829 हो गई है जिनमें से 1,28,829 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में है। प्रत्येक डाकघर औसतन 22.69 वर्ग कि. मी. क्षेत्र को और 4731 लोगों को सेवा प्रदान करता है। विभाग ने सातवीं योजना (1985–90) के दौरान 6000 नए डाकघर खोलने की योजना बनाई है। विभाग ने जो 6000 डाकघर खोलने की योजना बनाई है, उसमें से लगभग 5000 डाकघर वर्ष 1988–89 और 1989–90 के दौरान खोलने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक डाकघर खोलने में आसानी रहे, इसलिए 19.12.87 से डाकघर खोलने के मानदंडों को उदार बनाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए घाटे की अधिकतम अनुमत सीमा को छोड़ते हुए इन मानदंडों को और अधिक उदार बनाया गया है। पंचायतों के विकेन्द्रित प्रशासनिक ढांचे के अनुकूल, विभाग ने 'पंचायत डाक सेवक स्कीम' नामक एक नई स्कीम आरंभ की है जिसके अंतर्गत जिन पंचायतों/ग्राम सभाओं में डाकघर नहीं हैं, उन्हें अपने स्वयं के डाक सेवक रखने के लिए 150 रु. मासिक नकद अनुदान दिया जाता है। पंचायतों को डाक सुविधाएं प्रदान करने के लिए, देश के विभिन्न भागों में 3386 डाक सेवक नियुक्त किए गए हैं। अंतिम लक्ष्य यही है कि जितनी जल्दी संभव हो सके, उतनी जल्दी शेष 74,000 पंचायत ग्रामों में ऐसी सुविधा प्रदान कर दी जाए।

डाक (मेल) सेवा

डाक विभाग एक वर्ष के दौरान लगभग 500 करोड़ डाक मदों का निपटान करता है। डाक, देश में लगे 4,81,757 लेटर बॉक्सों से इकट्ठी की जाती है। उक्त लेटर बॉक्सों में से 4,01,156 ग्रामीण क्षेत्रों में और 80601 शहरी क्षेत्रों में हैं। डाक प्रेषण और वितरण के क्षेत्र में अपनी दीर्घ परम्परा और सुविज्ञता का उपयोग करते हुए विभाग ने 1986 में 'स्पीड पोस्ट' नामक एक गारंटीशुदा वितरण सेवा प्रारम्भ की थी जो बढ़ती हुई प्राइवेट कूरिअर सेवाओं का एक सस्ता पर अधिक विश्वसनीय विकल्प है। अगस्त, 1986 में प्रारंभ, इस सेवा के केवल 7 केन्द्र थे, जिनकी संख्या वित्तीय वर्ष 1987–88 के अंत तक बढ़कर 37 हो गई।

आधुनिक टेक्नालॉजी का उपयोग

हालांकि डाक विभाग के अधिकांश कार्यकलाप पारम्परिक मैनुअल तरीकों से ही सम्पन्न किए जाते हैं, तथापि, अपनी उत्पादकता को बढ़ाने तथा अपने उत्पादों और सेवाओं की मूल्य-रेखा को नियंत्रित रखने के लिए, विभाग आधुनिक टेक्नालॉजी अपनाने का प्रयास करता रहा है। काउन्टरों पर उपयोग करने के लिए बहुउद्देशीय मशीनों, डाक वस्तुओं का वजन मापने के लिए डिजीटल तुला, डाक शुल्क और उपभोक्ताओं को जारी रसीदों का परिकलन, डाक-टिकटों को विरूपित करने के लिए डाक टिकट विरूपण मशीनें विकसित की जा रही हैं और इनको शीघ्र उपयोग में लाए जाने की संभावना है। विभाग कर्मचारियों को विस्थापित करने के नाजुक प्रश्न का सम्यक् ध्यान रखते हुए अपने प्रचालन के ऐसे कतिपय क्षेत्रों में कम्प्यूटरों का उपयोग शुरू कर रहा है जिनमें कर्मचारी द्वारा स्वयं (मैनुअली) हिसाब-किताब करने की जटिलता शामिल है।

मोटर वाहन

एक कार्यकुशल डाक सेवा प्रदान करने के लिए विभाग के पास वाहनों का एक बेड़ा है जिसमें वित्तीय वर्ष 1987–88 के अंत तक 1053 वाहन थे। पिछले चार वर्षों के दौरान या तो पुराने वाहनों को बदलने के उद्देश्य से अथवा बेड़े में नए वाहन जोड़ने के प्रयोजन से 357 मोटर वाहन खरीदे गए।

डाक भवन

1.4.1988 को डाक विभाग के पास अपने 3473 भवन थे जिनमें डाकघर, डाक कार्यालय और प्रशासनिक कार्यालय स्थापित हैं तथा कर्मचारियों के लिए 20845 क्वार्टर थे। पिछले चार वर्षों के दौरान विभिन्न कार्यालयों के लिए 322 भवनों का और कर्मचारियों के लिए 4217 क्वार्टरों का निर्माण किया गया।

एजेंसी सेवाएं

डाक विभाग देश के विकास कार्यों के लिए धनराशि जुटाने के प्रयोजन से अल्पबचत योजनाएं चलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वित्तीय वर्ष 1987–88 के अंत में सभी प्रकार की बचत योजनाओं में बकाया शेष राशि 28400.7 करोड़ रुपये थी जो 1983–84 के अंत में जमा बकाया शेष से 110% अधिक थी। पिछले चार वर्षों के दौरान डाक जीवन बीमा पॉलिसी ने उल्लेखनीय लाभ अर्जित किया। 1983–84 के अंत में पॉलिसियों की संख्या 10.8 लाख थी जो 1987–88 के अंत तक बढ़कर 13.6 लाख हो गई थी और इस प्रकार इसमें 25.58 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1983–84 के अंत में पॉलिसियों पर बीमाकृत कुल राशि 809.4 करोड़ रु. थी जो 1987–88 के अंत में बढ़कर 1439.3 करोड़ रुपये हो गई और इस प्रकार इसमें 77.82 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

OVERVIEW

The last decade has witnessed an explosion in communications technology around the world. While our sister Department of Telecommunications in the Ministry is trying to absorb these dramatic changes, the traditional postal services provided by the Department of Posts have continued to be relevant to the masses of this country. The relevance and importance of Postal Communications for business houses, legal transactions and academic activities is well recognised even in super industrial societies. For this country, the Post Office is expected to be the back bone of communicative activity for many decades to come. Ninety-six per cent of the area of India is rural and seventy-seven per cent of our population live in rural areas. For all of us, the postal service is the main artery of message circulation and will continue to be so in the foreseeable future. The urban worker, the trade and commerce look upon postal service as user-friendly with a human face.

In spite of constraint of resources, the Department of Posts has continued to expand its network to provide services to the populace who in the recent past, had to walk miles before they reached a post office. The norms for the opening of post offices have been liberalised and the gram panchayat, which is the basic unit of decentralised administration, has become the focal point in providing postal facilities. An innovative method of 'Panchayat Dak Sewaks' who are employees of gram panchayats but are remunerated for performing postal work by the Department of Posts has been introduced to provide postal facilities in gram panchayat villages which cannot have a post office immediately.

The postal monopoly imposes an obligation on the Department of Posts to provide service at a uniform rate-be it communication within a city, between cities or across-the-country. Several private couriers, by offering a premium speedy service within a city or between cities to selected customers at a higher price, have tried to attract the profitable upmarket segments leaving the postal service to handle the more expensive long distance transportation and delivery services. The Department of Posts has vigorously responded to this challenge by introducing a premium service with assured delivery within 24 to 72 hours called "SPEED POST" which connects 50 cities in the country. This service is also being used for sending Money Orders. Efforts were also initiated for Postal managers to work more closely with major customers so that the Postal Service is today better able to understand and anticipate their needs. The Postal Service is also gearing itself to assimilate the technological opportunities provided by FAX, Satellite Communication and mechanical handling of mail. These methods will not only make the services speedier but also reduce costs and help the Department in holding the price-line of its products and services for the benefit of the common man.

The finances of the Department continue to cause anxiety. Though the Government has never looked upon the Postal Service as an institution for producing profits or generate resources, the expectation is that the service should pay its way through or atleast contain its losses within an acceptable limit. In an era of rising costs, especially man-power costs in a labour-intensive organisation like the Postal Service, and in the context of a conscious policy of maintaining the prices of postal products and services below their actual costs, this is an extremely tall order. Yet the Postal

Service during 1987-88 has succeeded in bringing down the deficit to 1900 million rupees from 2160 million rupees in 1986-87. The Government, the Planning Commission and the Finance Commission have stressed the need to reduce the revenue deficit in order to find resources for the Seventh and Eighth Plans. The Department of Posts will, therefore, continue to reduce costs by absorbing a considerable portion of volume growth through increased productivity, but it may also narrow the gap between prices and costs in a graduated manner without over-burdening the users of the Postal Services.

Technology and finance, of course, will not move mail by themselves. The Postal Service continues to rely on the effort of its employees numbering about 600 thousand. Its men and women remain committed to its long tradition of public service, but they recognize that the competitive environment in which the Postal Service finds itself requires that it innovate and work harder to win and keep its customers. By removal of acrimony in collective bargaining, by constant discussion and exchange of ideas, the Postal Service will succeed in earning their support to its growing commitment to customer-focused service initiatives, introduction of new technology and cost-containment.

The Postal Service, in spite of all its handicaps, has striven constantly to provide one of the most fundamental public services of this country efficiently and honestly. Through change and innovation, this basic tradition of public service will continue to flourish.

IMPROVING POSTAL OPERATIONS

Goals

The thrust of the Department of Posts during the year has been on improving the quality and spread of the service and maximising customer satisfaction. Our entire operational set up is geared towards achieving these ends. During the year under review, the existing network was strengthened and several new measures were initiated to ensure greater customer satisfaction and acceptability.

Expansion of the postal net work

The postal network as on 31-3-1988 consisted of 1,44,829 Post Offices, of which 1,28,829 were in the rural areas and 16,000 in the urban areas. Each Post Office serves, on an average, an area of 22.69 sq. kms and a population of 4731. At this level of development, the country is well within the norms adopted by the Universal Postal Union (UPU) that there should be one Post Office to serve on an average either an area of between 20 to 40 sq. kms. or 3000 to 6000 inhabitants. There were 4,81,757 letter boxes in the country, out of which 4,01,156 were in rural areas and 80,601 in urban areas. The Seventh Plan of the country envisaged opening of 6,000 new Post Offices in the rural areas, the bulk of which are to opened in 1988-89 and 1989-90. In order to achieve this target, the Department liberalised the norms for opening of Branch Post Offices in rural areas with effect from 19-12-87. The revised norms are:

- A group of villages constituting a gram panchayat or village council will be eligible for a Post Office provided that (a) the aggregate population of the group of villages is not less than 1,500 in hilly, backward and tribal areas and (b) there is no post office within the group.
- No new post office should normally be opened within 3 kms. of an existing post office. This restriction is, however, relaxable in hilly areas.
- The anticipated revenue of a proposed post office should not be less than 33 1/3% of its cost in normal rural areas and 15% of its cost in hilly, tribal and backward areas.

In order to align the availability of postal services with the decentralised administrative set up in the rural areas, the Minister of Communications announced in Parliament on 24-2-88 that -

> In keeping with the pressing demand from the Hon'ble Members and also the public at large, the Government desires to undertake a massive programme of postal facilities in each one of the remaining 74,000 panchayat villages in next two years.

In order to implement this policy, the Department has introduced a new scheme called "Panchayat Dak Sewak Scheme".

NUMBER OF POST OFFICES

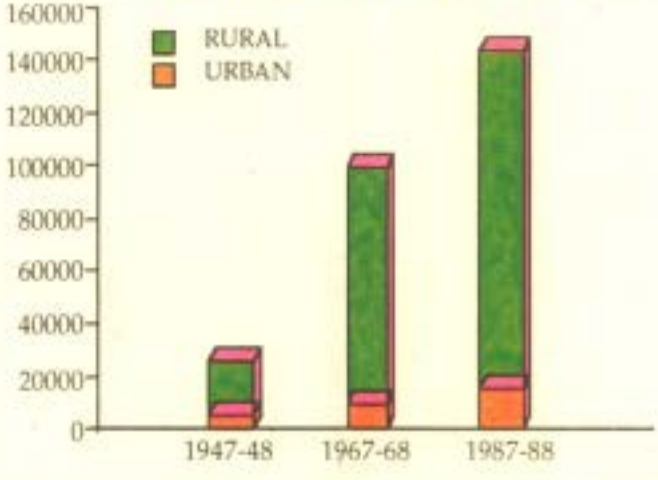

Mails

The postal traffic continues to show a steady growth. During the year the Department handled nearly 5000 million pieces of mail.

POSTAL TRAFFIC SINCE 1979-80 (ADJUSTED TO REVENUE)

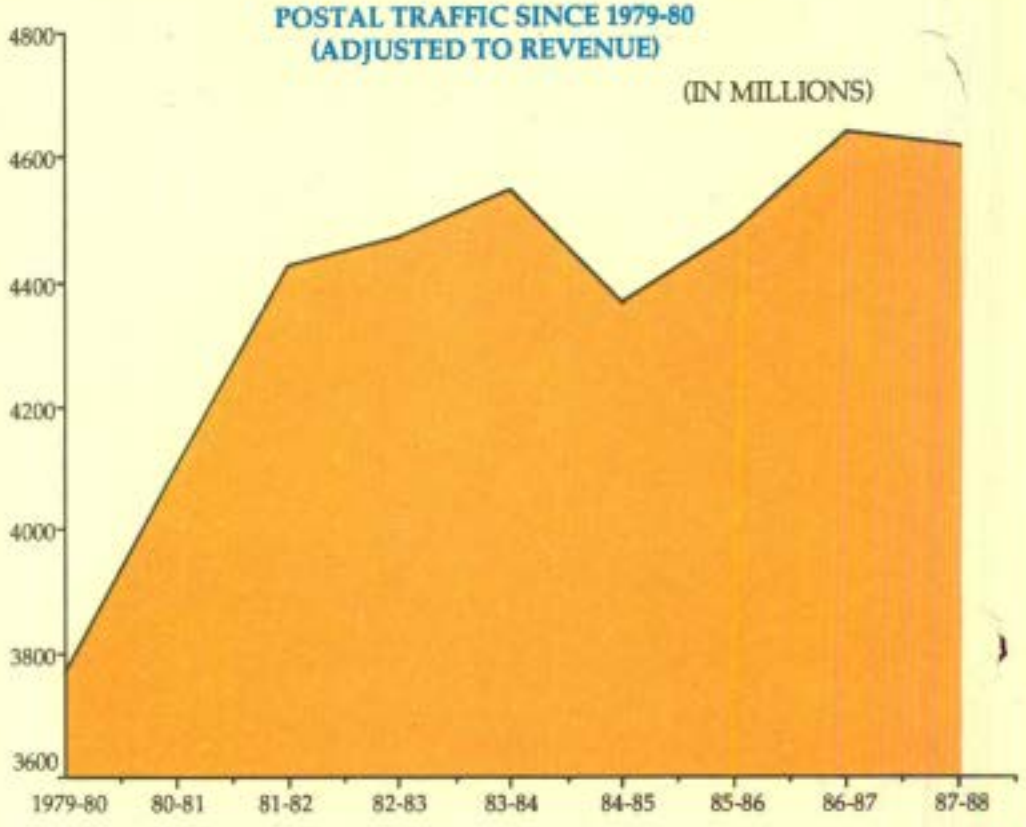

ARTICLEWISE POSTAL TRAFFIC

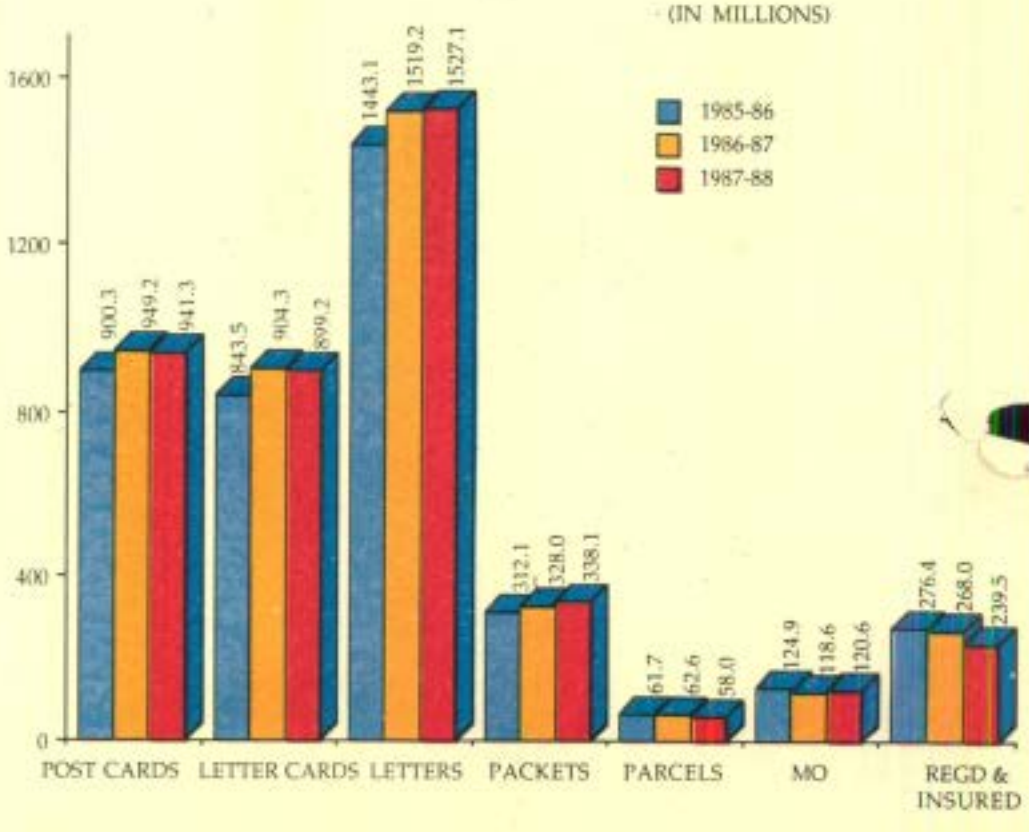

In order to monitor the efficiency of the delivery system, live mail sampling was introduced on a national basis. 23% of the mail is delivered on the day following the day of posting (D+1), 25% on the second day following the day of posting (D+2), 29% on the third day following the day of posting (D+3), and the remaining 23% on the fourth day following the day of posting (D+4). These percentages reflect the total mail for delivery and not just the articles which can be delivered in D+1 or D+2, etc.

The Department is now facing competition in some areas of its traditional operations. While the Department has the monopoly over the transmission of letter mail, private couriers have claimed a share of the market for transmission of documents and parcels. Making use of its long tradition and expertise in the area of transmission and delivery of mails, the Department introduced a guaranteed delivery service in 1986 called "SPEED POST" as a cheaper and more reliable alternative to the private courier services. During the year under review, the Speed Post service was enlarged to include 23 more centres, thus bringing the total number of centres in the country to 37. The scope of the service itself was enhanced to include money orders which could be sent from one place to another at a nominal additional cost. The traffic analysis of the Speed Post service reveals customer acceptability and growing utilisation. Thus, starting from a modest 68264 articles in 14 Speed Post Centres in April 1987, the traffic had increased to 130662 articles by March, 88 from 37 centres and 7 extension counters showing a growth of nearly one hundred per cent. Traffic figures of individual centres also reveal great acceptability and use of the Speed Post.

In the international area the Speed Post Service was linked to 20 countries.

SPEED POST TRAFFIC (DOMESTIC)
(IN THOUSANDS)

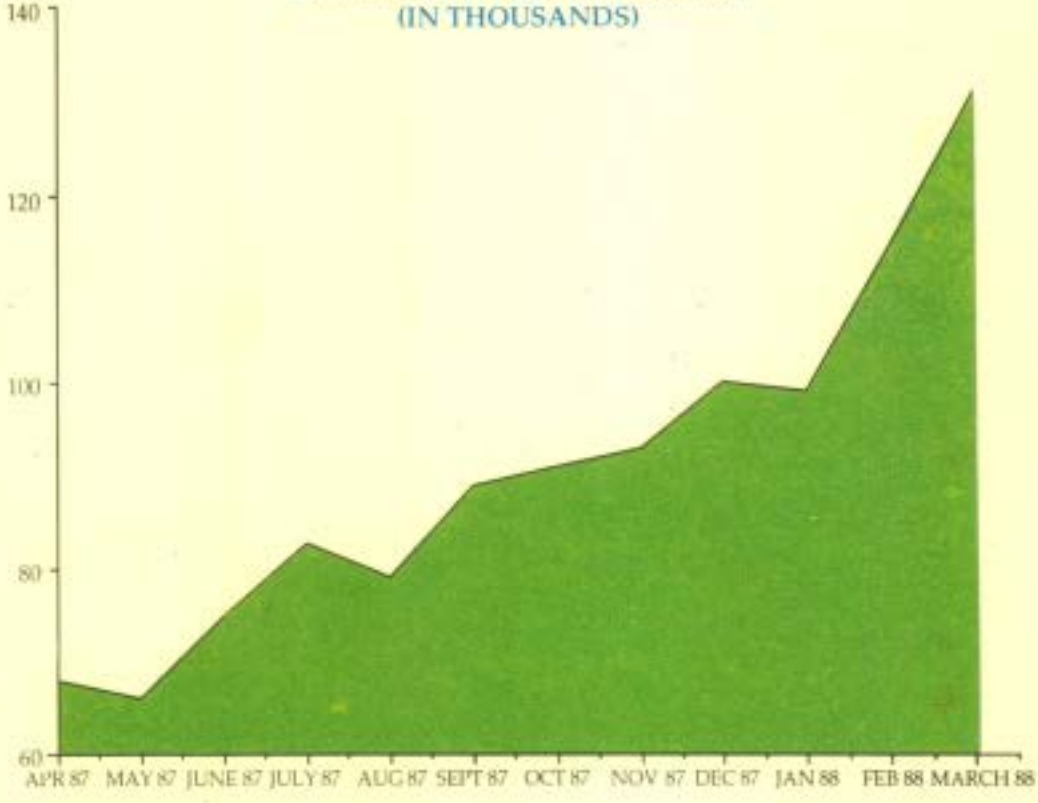

Technology Upgradation

The Department is alive to the possibility of improving its customer services and increasing productivity through application of technology in appropriate areas. Two broad areas identified for technology application are internal office working and public inter-face. For internal office working

simultaneous start has been made for computerisation at Bangalore, Madras and Delhi. The computer at Bangalore is dedicated to Postal Life Insurance and the one at Madras is handling money order pairing work. At Delhi, computers are used for money order pairing, international mail accounts and Savings Bank. Based on the experience with these pilot projects, plans are afoot for greater utilisation of modern technology to streamline the internal working of the Department.

High speed stamp cancelling machines have been developed indigenously and 40 such machines have been supplied to busy post offices during the year. These high speed machines not only remove the drudgery of manual operation but also replace the existing hand stamps which wear out early and give smudgy and illegible impressions. Since hand stamps will continue to be used in smaller offices, methods of improving hand stamps on trial basis were developed by the Central Postal Machines Workshop, New Delhi and 20 improved stamps and seals are being tried out in Delhi. With the trial run proving successful, the manufacture of these stamps will be undertaken at New Delhi and Aligarh. Polymer as an alternative to steel used in stamps is likely to be cheaper, more durable and capable of giving better impressions. 136 hand stamps using polymer instead of steel were imported from France and are being tried in selected Post Offices. Steps have been taken for their indigenous manufacture.

With 18% to 20% of the total mail traffic of 5000 million pieces originating or terminating in the four metropolitan cities, it is becoming increasingly difficult to handle metropolitan mail manually. Bombay has been selected for the first phase of the introduction of automatic mail processing in the metropolitan towns. The project for Bombay has been approved and global tenders for finalisation of the project will be floated shortly.

In the area of public inter-face, the Department has succeeded in introducing a micro processor-based machine which is capable of booking parcels, money orders, registered letters, VP articles as well as Speed Post articles at the same counter. After prototype trials, such machines are expected to be widely used in the post offices shortly. Digital weighing scales, capable of displaying the weight and postal charges appropriate to the weight of articles, have also been developed. These devices will tremendously improve the customer services at the postal counters.

Postal Premises

One of the thrust areas of improving postal operations is to provide specially-designed spacious buildings to the post offices. During 1987-88, an outlay of Rs. 30 crores was made for this purpose. Construction of 109 post office and mail office buildings was started and 68 post office buildings were completed. Another 264 post office and mail office buildings were at various stages of construction. During this period, construction of 283 staff quarters had started and 952 staff quarters were completed and 950 staff quarters were under construction. At the end of the year under review, out of 25866 departmental post offices, 3179 or 12.29% of the total number of post offices were functioning in departmental buildings.

Savings Bank

The public continues to repose its faith in the Post Office Savings Bank which is one of the biggest banks in the country, operating through a wide network of 1,44,084 Post Offices. With a view to providing better services to the depositors and to bring about economy in operation, various measures were undertaken in the year 1987-88. They are -

— Premature closure of Cumulative Time Deposit accounts is permitted now without any reference to the maximum holding;

— Maximum limit of deposit in Savings Account has been raised from Rs. 25,000 to Rs. 50,000 in single account and from Rs. 50,000 to Rs. 1,00,000 in joint account;

— Post Offices in Lower Selection Grade and above have been authorised to close individual savings accounts. This will provide better facilities to the public and reduce the time taken in closing individual accounts.

OUTSTANDING BALANCES IN ALL FORMS OF SAVINGS

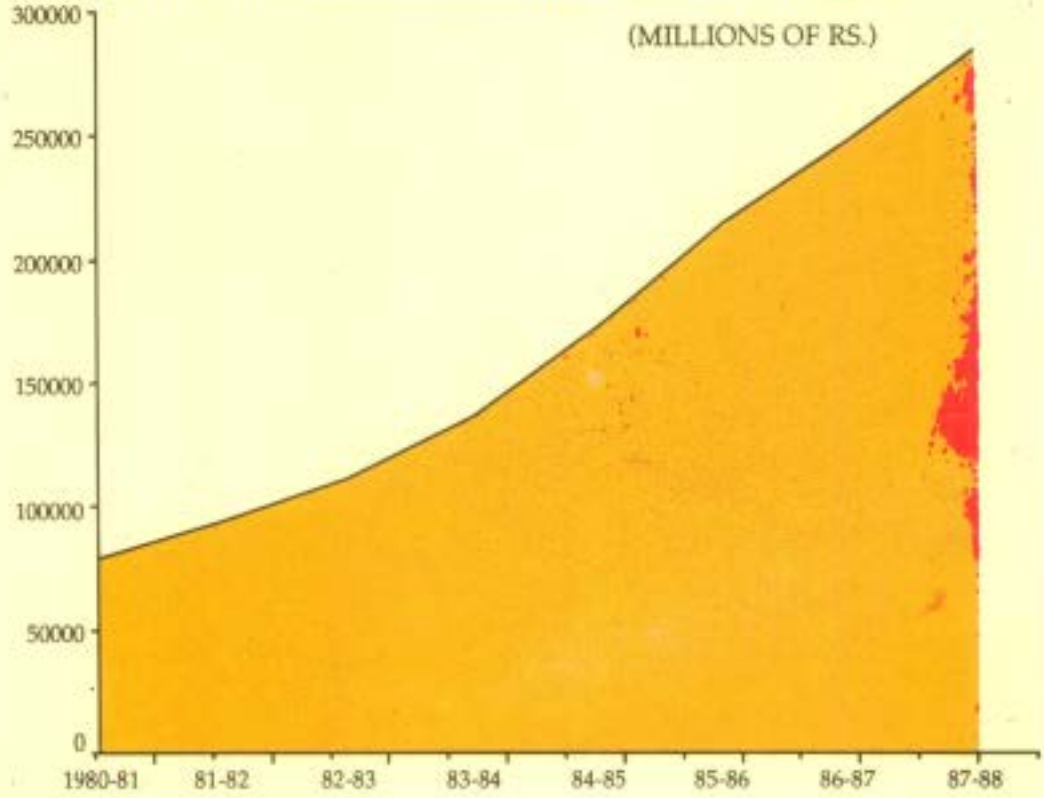

NUMBER OF ALL KINDS OF SAVINGS ACCOUNTS

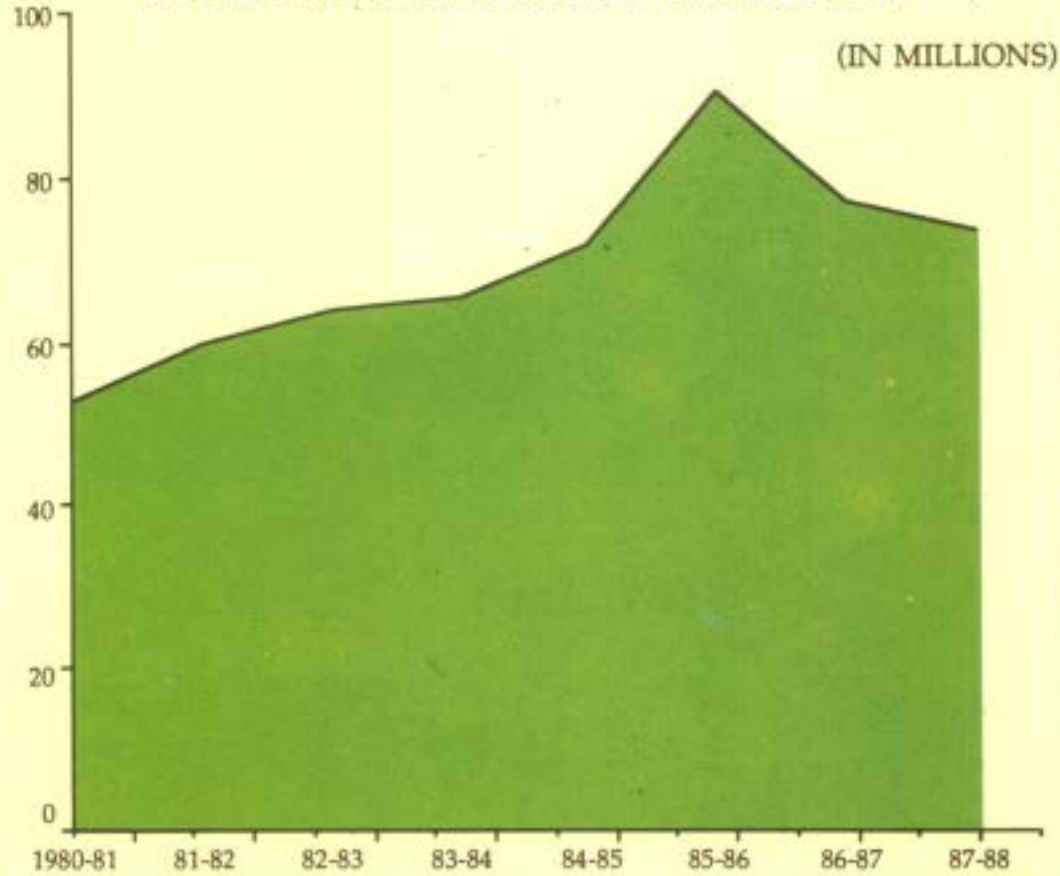

For the benefit of Income tax payers, a National Savings Scheme has been introduced with effect from 1-4-1987. In this scheme, the entire amount deposited in such an account, subject to a limit of Rs. 30,000/- in the year 1987-88, is exempted from Income tax under Section 80-CCA of the Income Tax Act.

A new scheme called the P.O. Monthly Income Account Scheme has been introduced with effect from 15-8-87. The scheme is attractive for retiring persons, pensioners, and other persons who desire to have a regular monthly income. The scheme is open to individuals only. The minimum deposit is Rs. 5000/- or multiples there of subject to a maximum of Rs. 2 lakhs in a single account and Rs. 4 lakhs in a joint account. Maturity period is six years and interest at the rate of 12% is payable monthly.

A new denomination of Indira Vikas Patra of Rs. 200/- has also been introduced.

The process of enrolment of Head Post Offices as full members of local Clearing Houses was continued during 1987-88. 202 Head Post Offices have become full members of the local Clearing Houses.

Postal Life Insurance

Like the Savings Bank, the Postal Life Insurance continues to show an upward trend both in terms of number of policies as well as the premium per policy.

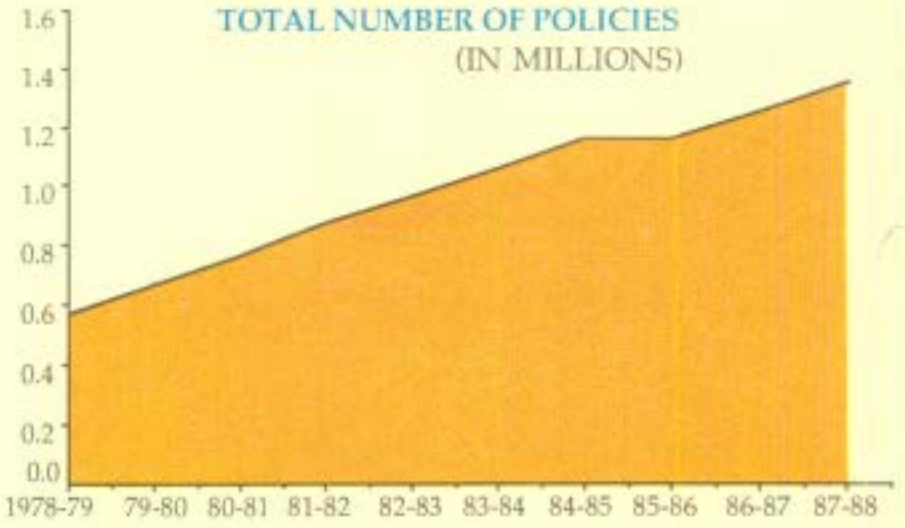

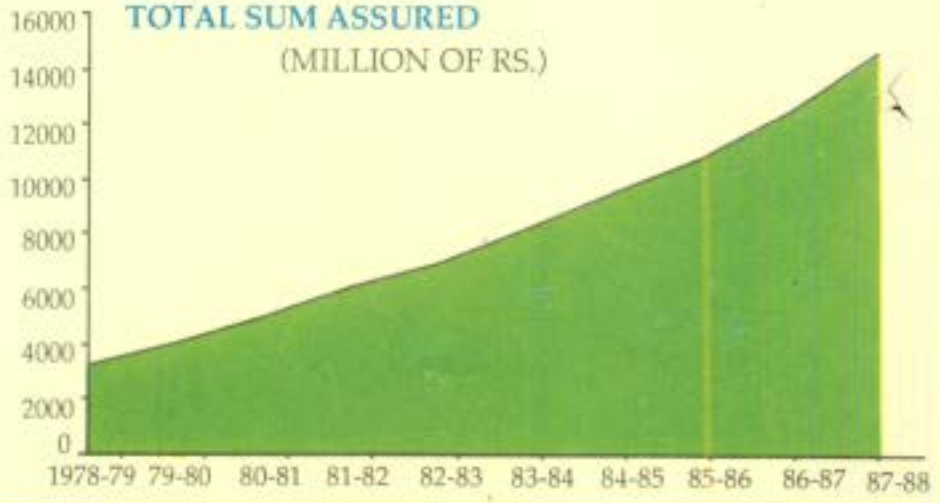

POSTAL LIFE INSURANCE PREMIUM

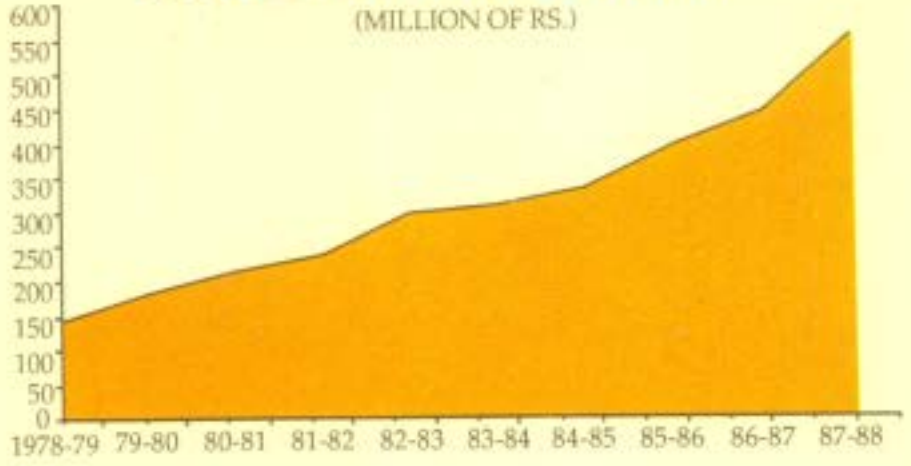

Philately

In the field of philately, preparations were started for holding INDIA 89 World Philatelic Exhibition from 20-29 January, 1989 in New Delhi. To commemorate the exhibition, two special stamps were issued in June, 1987 depicting the logo of the exhibition and the venue of the exhibition. Four more stamps were also issued in October, 1987. Two miniature sheets were also brought out to commemorate the exhibition. Including these six stamps, 62 commemorative/special stamps were issued during the year. In order to encourage and promote philately, three State level exhibitions were held in Orissa, Tamil Nadu and Rajasthan. The Department also participated in three International Philatelic Exhibitions, namely "CAPEX" (Canadian Philatelic Exhibition), "HAFNIA" (The Danish Philatelic Exhibition) and "THAIPEX" (Thailand Philatelic Exhibition). A large number of special cancellations as well as special covers were also released through 45 Philatelic Bureaux and 142 Philatelic Counters in the country.

Public Complaints

Complaints about traffic delays showed a decrease from 776210 in 1986-87 to 711925 in 1987-88. Complaints as a percentage of total traffic handled was 0.00525%. While in percentage terms the complaints are negligible and the Department has reason to have a sense of satisfaction, yet conscious efforts were made to treat each complaint as a reflection on the total service and to ensure that bottlenecks were removed. The Department continued to work in close liaison with the Administrative Reforms and Public Grievances in monitoring persistent complaints.

Improvement of Postal Procedures

Efforts were also made to rationalise operational procedures. In order to bring about clarity in the existing procedures and prevent loss of revenue, certain categories of articles like commercial items which bear manuscript, rubber stamped, type-written, bradma printed or computer printed entries have been excluded from the definition of Book Post.

Historically, unpaid and underpaid articles received in Post Offices have been treated as part of its cash balance because the volume of such traffic in the past was large. This procedure of including a very small amount of postage due as part of the large cash balance of an office has outlived its utility. This procedure has now been changed and only the actual revenue collected is accounted for as a receipt, thereby greatly simplifying the account records at different stages.

HUMAN RESOURCES

Manpower Employment

With such a widespread network serving the needs of people all over the country, the Department has to rely on the efficiency, hard work and sincerity of its staff. The Department continued to be one of the biggest employers of the Government, accounting for about 8.93% (as on 31.3.86) of the Central Government establishment. The total staff strength as on 31.3.88 was 589798 comprising 291 thousands regular employees and 298 thousands extra-departmental employees.

DEPARTMENTAL STAFF STRENGTH SINCE 1978-79

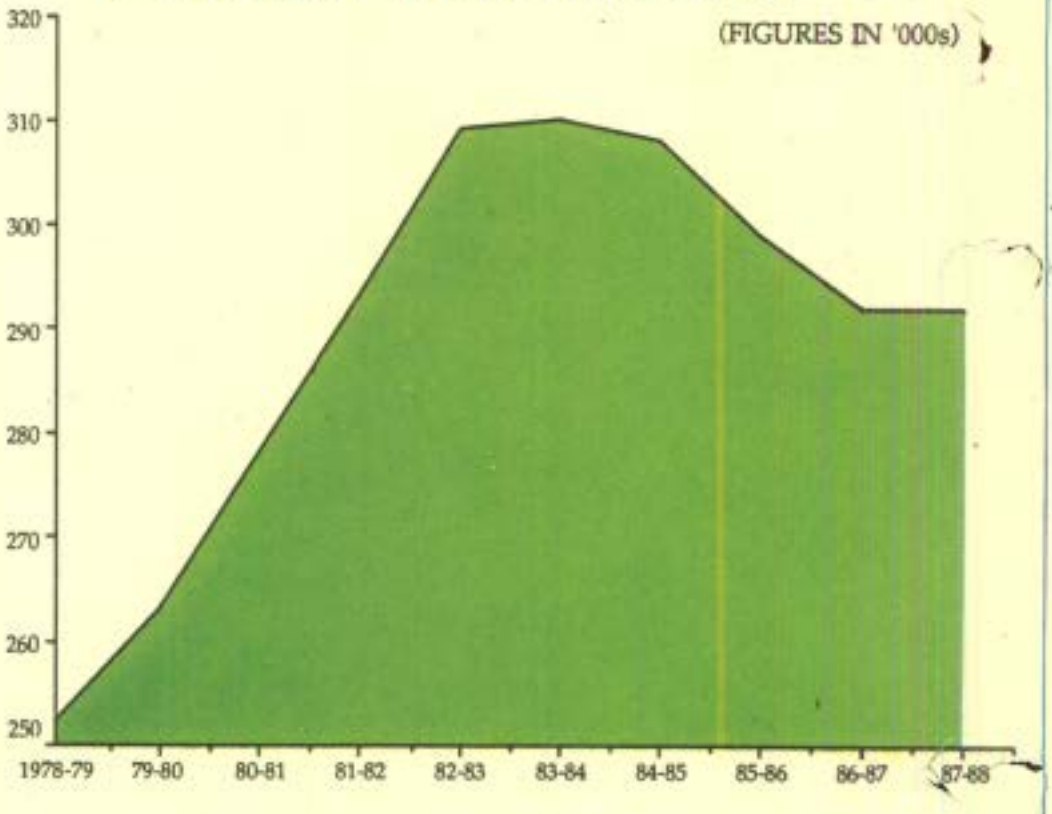

Employees Remuneration

In order to ensure the well-being of such a large staff component, the Department has undertaken several measures to ensure their well-being. As a result of the Fourth Pay Commission's recommendations, there was a general increase in the salary of all employees of the Department.

The remuneration of Extra Departmental Employees was also increased. They have been brought on par with regular departmental employees in the matter of Dearness Allowance which is now sanctioned to them as and when Dearness Allowance is sanctioned to the regular employees.

STAFF STRENGTH AS ON 31-3-1988

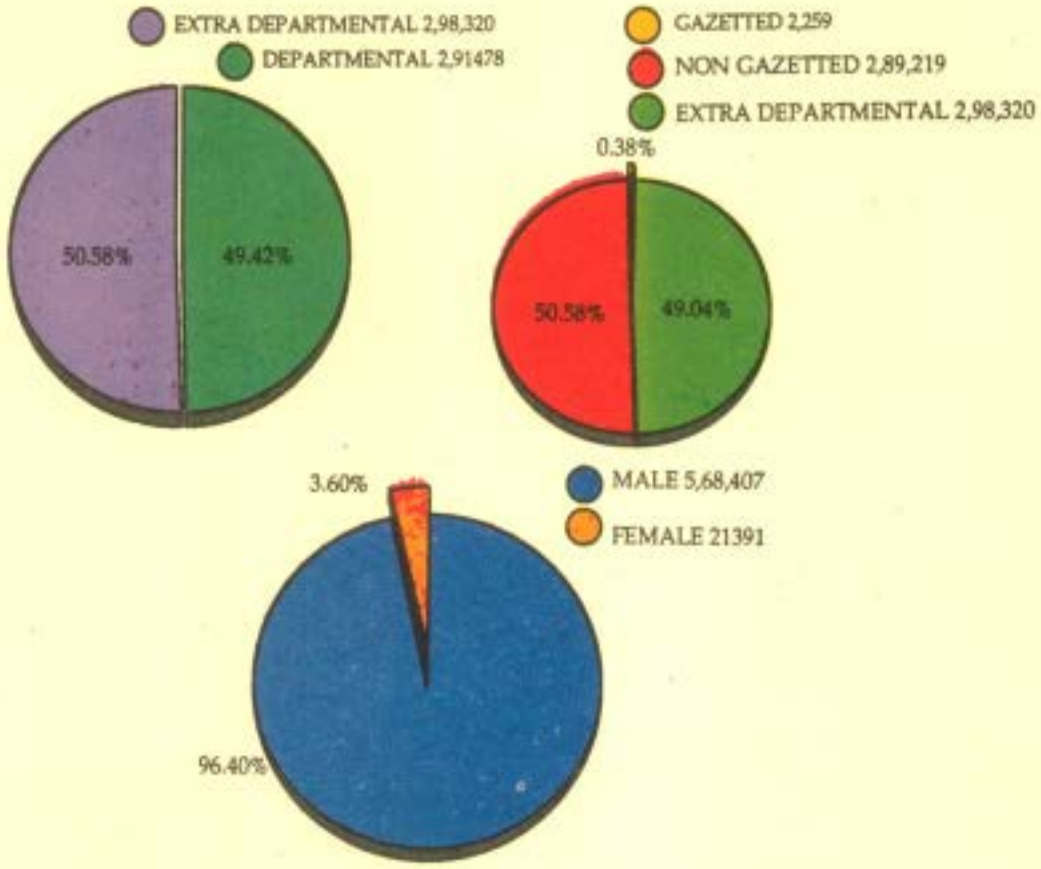

	BASIC ALLOWANCE 1.1.1986		REVISED BASIC ALLOWANCE	
	Min.	Max.	Min.	Max.
E.D.S.P.Ms	310	373	385	620
E.D.B.P.Ms	217	265	275	440
Other EDAs, EDDAs, EDMCs (etc.) for less than 2 hours	191	(fixed)	240	(fixed)
For two hours and more	214	254	270	420

The other allowances, which were being paid to the EDAs have also been revised as below:

Name of allowance	Existing Rate	Revised Rate
Delivery & conveyance allowance to EDBPMs	Rs.15/-	Rs.50/-
Cycle allowance	Rs. 8/-	Rs.20/-
Office maintenance allowance	Rs.10/-	Rs. 25/-
Fixed stationary charges to EDBPMs	Re. 1/-	Rs. 3/-

Training

Training of staff has been one of the thrust areas of the Department. There are five Regional Training Centres which provide induction and inservice training to operative and supervisory staff. During the year, about 7000 officials were imparted such training. The Department's national level institution, the Postal Staff College, provides induction training to the directly-recruited officers of the Indian Postal Service and Indian P&T Finance

and Accounts Service. 130 officers of different cadres attended the training programmes conducted by the Postal Staff College including refresher courses, seminars, workshops and Executive Development Programmes.

The Training Centres were also used for training officers of other countries. The Postal Staff College conducted a programme for 11 officers of SAARC countries. A course of Modern Management was held at the Postal Training Centre at Mysore for middle grade officers from Ethiopia, Sierra Leone, Surinam, Uganda, Yemen, and Liberia. In addition, the Training Centres undertook a comprehensive review of all training syllabus and material for various cadres. They also conducted a nationwide survey covering more than 10,000 postal employees of all cadres and more than 5000 consumers. The feedback obtained from these surveys was utilised to redesign training programmes.

Staff Relations

The Department of Posts has recognised 29 Unions/Associations including three Federations to represent the Postal employees. During the period from April 1987 to March 1988 there were some occasions of disturbed relations between the Unions and the Administration which included a joint notice of strike from 14-7-1987 to 20-7-1987 given by the three Federations for settlement of a 13 Point Charter of Demands. Another Union representing Postmen and Group 'D' employees also gave a strike notice in the month of November 1987 regarding the demands of ED employees. One Union staged dharna at Dak Bhawan twice for settlement of certain demands of ED employees.

The differences between the Administration and the Unions over various matters were resolved through mutual discussions and meetings as a result of which both the strike notices were withdrawn and the dharnas also were discontinued. The most notable event which took place during this period was a memorandum of settlement signed by Secretary, Department of Posts with the three Federations on 11-7-1987 over a number of demands which were agitating the minds of postal employees. After this settlement, industrial harmony prevails in the Department on all sides.

Meetings of the Departmental Council (JCM) were held on 7th and 8th September, 1987 and 28th and 29th January,1988. 51 items were discussed in the meeting of the Departmental Council held in September, 1987 and 67 items were discussed in the subsequent meeting of the Departmental Council held in January, 1988. In addition, various periodical meetings were also held with the Federations and non-federated Unions/ Associations in which a number of pending demands of the employees were settled.

National Postal Awards

Recognition and appreciation of meritorious service rendered by the employees is an important motivational strategy. With this end in view, National Postal Awards known as 'Meghdoot' Awards were instituted in 1984. Awards are also given at Circle level. These are known as 'Dak Sewa' awards.

The awards are made to the following categories of the staff who are selected on the basis of recommendations of the Heads of Circles:

- Extra Departmental Employees of all categories.
- Group 'D' officials, postmen or equivalent rank.
- Group 'C' officials working as Head of an Office like post office, mail office, etc.
- Postal and Sorting Assistants.
- Supervisory officials in LSG, HSG, Inspectors, Asstt. Supdt. of all categories.
- Women employees belonging to any of the above categories.

The following employees of the Department of Posts were presented 'Meghdoot Award' for excellence in performance for the year 1986-87 on 9th October, 1987 by Shri Arjun Singh, the then Minister of Communications on the occasion of World Post Day at Salem (Tamil Nadu):

- Shri Jogga Ram, ED Runner (Himachal Pradesh).
- Shri P. Girirajan, Postman, Madras.
- Shri N. Divakaran, Office Assistant,

Ernakulam (Kerela)
- Shri Ramachandra Panda, LSG Sub Postmaster, Cuttack, (Orissa).
- Shri M.V. Pendse, LSG Supervisor, Foreign Mail, Bombay.
- Smt. Darshana Devi, E.D. Branch Postmaster, Sriganganagar (Rajasthan).

Health Care

In order to look after the health needs of the staff, the Department of Posts runs 54 dispensaries which are functioning at 45 stations in the country and provide extensive outdoor medical facilities including domiciliary visits, routine laboratory tests and supply of medicines. The dispensaries also cater to the employees of the Department of Telecommunications. The dispensaries provide timely and adequate medical facilities to the employees and their family members.

Welfare

For a large manpower-employing organisation like the Department of Posts, welfare of personnel is of paramount importance. Keeping this in view, a Postal Service Staff Welfare Board has been constituted under the Chairmanship of Minister of Communications. The objectives of the Board are to promote and develop staff amenities and welfare, sports and cultural activities in the Department. During the year, a sum of Rs. 66 lakhs was disbursed as financial assistance in the cases of illness/death, educational scholarships, sports cultural events, recreation clubs, etc.

The rates of scholarships for the children of the employees, financial assistance to employees who go on long leave due to illness and grants of TB patients were enhanced. The limits of eligibility for grants of scholarships were also revised. Holiday Homes have been established at 16 places to provide rest and recreational facilities to the employees.

Sports meets were conducted at Divisional, Regional and all-India levels in 15 different disciplines during the year. Sportsmen from the Department participated in National Championships in 11 events like Volleyball, Wrestling, Chess, Weightlifting, Table Tennis, Kabaddi and Athletics. A chess player from Bihar Circle participated in the Lloyds Bank masters Chess Championship in October 1987. An All-India Cultural Meet was also organized at Bangalore in which children and families of postal employees exhibited their talents.

Scheduled Castes & Scheduled Tribes

The Department is implementing in full the existing Government orders for observing relaxed standards for the recruitment of SC and ST candidates, particularly in the Departmental qualifying examinations.

Keeping in view the need for providing adequate encouragement to the SC and ST candidates, the Department has further decided that when the required number of SC/ST candidates do not qualify even under the relaxed standards, the cases of the failed candidates should be reviewed on the basis of their confidential records of service and overall performance in the examination. This review is carried out by a Committee of senior officers primarily to ascertain the suitability of the candidates for higher responsibility. Those candidates who are considered not unfit for promotion are allowed grace marks wherever required, to bring them up to the qualifying standard. Thus, the Department has made special efforts in keeping with the spirit of the existing orders to provide fillip to SC/ST candidates for their career advancements.

Adequate attention is also being given to the implementation of the Prime Minister's 15-Point Programme for minority welfare. The recruiting units in the Department are submitting quarterly statements directly to the Minority Cell, Department of Welfare indicating the percentage of different minority communities recruited during each quarter. The performance of the Department in this regard has been viewed as satisfactory by the concerned monitoring authorities.

PERCENTAGE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES EMPLOYEES (1987-88)

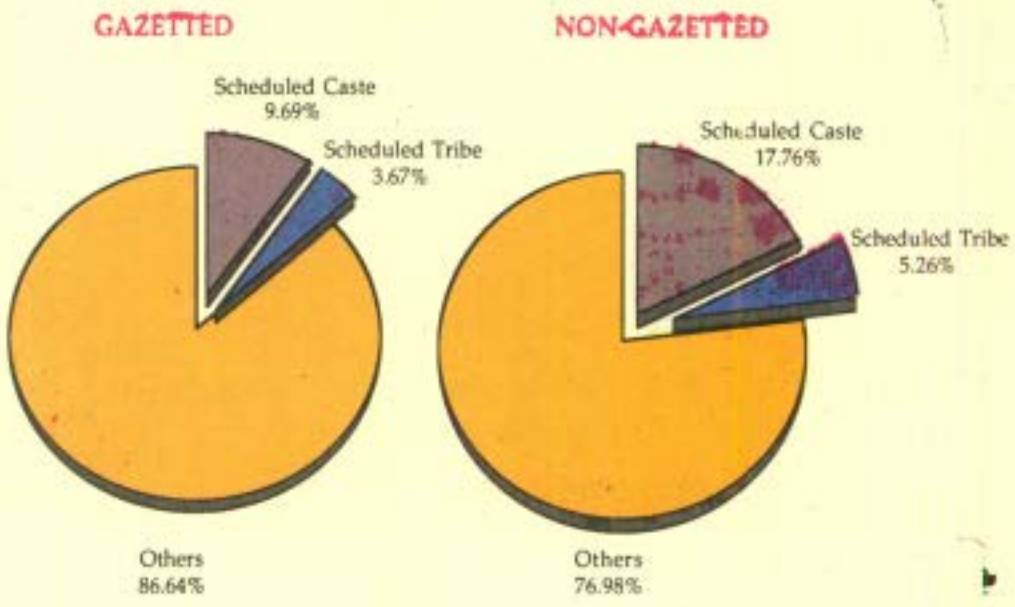

Work Study and Method Study

The Department has an Internal Work Study Unit which carried out time and motion studies relating to norms for staff assessment in field units and work measurements and method studies. During the year, studies were completed for:

- Revision of norms for creation of Head Post Offices.
- Evolution of norms for Group 'C' staff and supporting staff connected with the work of Franking Machines in Main Post Offices and second office of posting.
- Evolution of norms for sanctioning Group 'C' staff connected with sales of Indra Vikas Patras in Post Offices.
- Evolution of norms for Group 'C' staff connected with the payment of pension under provision of Coal Mines Family Pension Scheme, 1971.
- Evolution of norms for Group 'C' staff with Administration Branch of Foreign Post.
- Sample Survey of Postal Traffic.
- PMR, PRP, Vig.III, UPE, C&A/Pay Bill and SB Sections of the Postal Directorate.
- Method study of PE-I and PE-II Sections of the Postal Directorate.

Use of Hindi in Official Work

Hindi, as the official language, is being progressively used in the official work of the Department. Vigorous action has been taken to maximise the use of Hindi. The Official Language Implementation Committee held four meetings during the year to review the implementation of the various provisions of the Official Language Act. The Hindi Salahkar Samiti attached to the Ministry of Communications under the Chairmanship of Minister of Communications continued to provide guidance and suggestions for the progressive use of Hindi in the Department.

Thirty-five officers were sponsored for Hindi training under the Hindi Teaching Scheme. A timebound programme for training of typists and stenographers working in the Directorate General of Posts in Hindi typing and Hindi stenography has been introduced and employees are being sponsored for this training. Three Workshops were also conducted for officers and officials of the Directorate in Hindi noting and drafting. During the year, 54 offices were notified where 80% or more staff had acquired working knowledge of Hindi. Eleven

Departmental Manuals were printed in diglot form while eight more are under print. A comprehensive list of readable Hindi books was prepared and recommended to the Circles for purchases for libraries.

A Hindi Week was organised in the Directorate from 7.12.87 to 11.12.87 and in the subordinate offices from 14.9.87 to 18.9.87. Prizes were given to the employees for doing their officials work in Hindi during the week. An all-India Official Language Conference was organized on 28.8.87 in which several important issues concerning the development of Hindi and increasing its use in official work were discussed. The second Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language visited a number of subordinate formations of the Department during the year and also Directorate on 23.12.87. The shortcomings noticed by the Committee were looked into and efforts are being made to remove them.

POSTAL FINANCES

From 1960-61 the Postal Service, which was earlier able to balance the revenue and expenditure without becoming a burden on the general exchequer, gradually started slipping into the red. While the cost of operations kept on mounting, the rates of various postal services either remained static or were raised only marginally but were kept well below their economic cost. The consequential deficits were made good by the Telecommunications Service without imposing a burden on the general exchequer. With the bifurcation of the P&T Department from 1.1.85, the scope for cross-subsidization of Postal Services from the surpluses of the Telecommunication Service within the Department has disappeared. The deficit in the operations of the Postal Services has now become a burden on the general exchequer.

During the last three years of our functioning as a separate Department, the Postal Services have incurred a net revenue deficit of Rs. 1635.5 millions, Rs. 2164.3 millions and Rs. 1908.7 millions during the years 1985-86, 1986-87 and 1987-88 respectively.

In spite of the revision of the prices of a number of Postal Services from 1.1.87, the cost of various services continued to be higher than the revenue earned by them. The revenue in respect of almost all services was significantly lower than the direct costs. If the overhead costs on account of general administration, accounts, storage and distribution, etc. were allocated on the entire range of postal services, their costs would still be higher than the revenue earned by them.

REVENUE AND EXPENDITURE

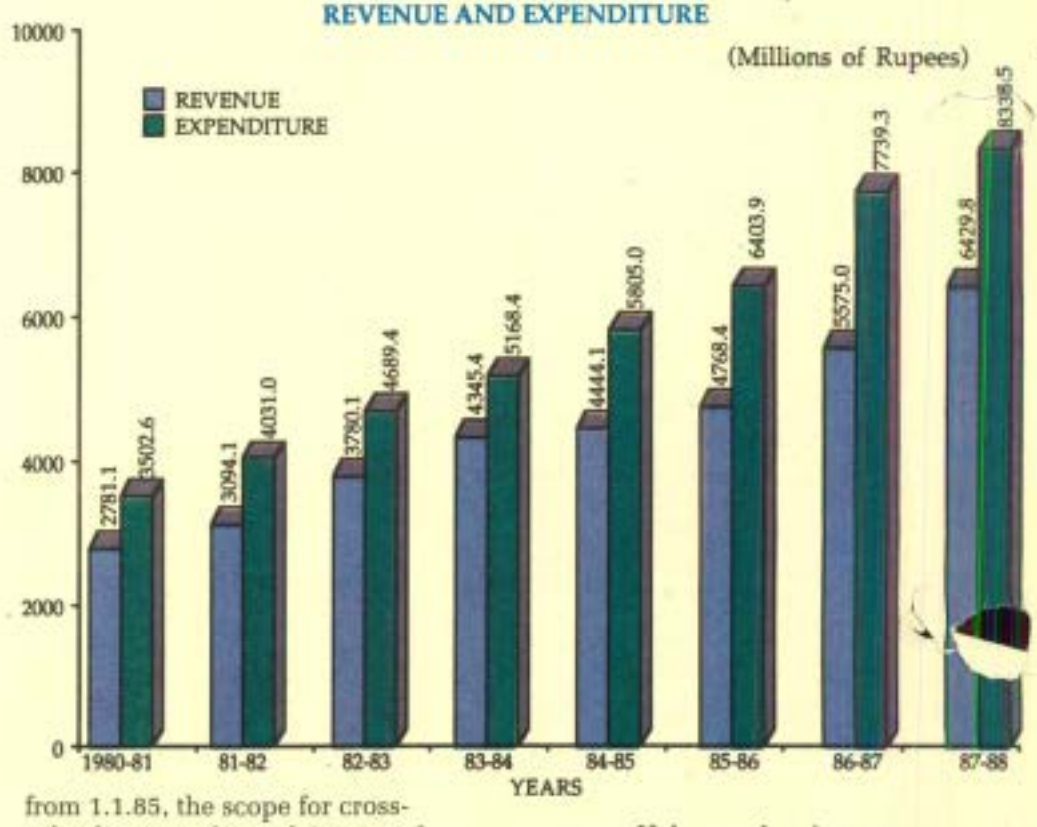

Name of Service	Direct unit cost (in paise)	Average revenue (in paise)	Deficit Gain per unit (in paise)	Total (in million of Rs.)
Post Cards	70.09	20.50	49.59	-466.1
Letter Cards	78.75	35.00	43.75	-393.8
Letters	92.66	100.00	+7.34	+94.7
Registered Newspapers				
Single	127.59	21.00	106.59	-234.5
Bundle	184.25	46.00	138.25	-55.3
Book Packets				
Book patterns & sample packets	137.57	81.00	56.57	-124.5
Printed Books	193.59	81.00	112.59	-56.3
Other Periodicals	220.69	100.00	120.69	-70.00
Recorded Delivery	311.32	207.00	104.32	-07.1
Parcels	957.43	903.00	54.43	-32.7
Registration	654.45	320.00	334.45	-769.2
Value Payables	831.41	260.00	571.41	-45.7
Insurance	1424.98	770.00	654.98	-59.7
Acknowledgements	63.63	74.00	+10.37	+18.1
Money Orders	629.73	650.00	+20.27	+24.4
Telegraphic Money Orders	830.00	285.00	545.00	-14.7
Indian Postal Orders	360.54	60.00	300.54	-70.00
				-2262.4
Overheads:				
Administration				698.0
Accounts				201.4
Audit				16.7
Storage & Distribution				37.0
				-3215.5

AVERAGE COST AND AVERAGE REVENUE OF SELECTED POSTAL ARTICLES FOR THE YEARS 1985-86, 1986-87 AND 1987-88 (in paise)

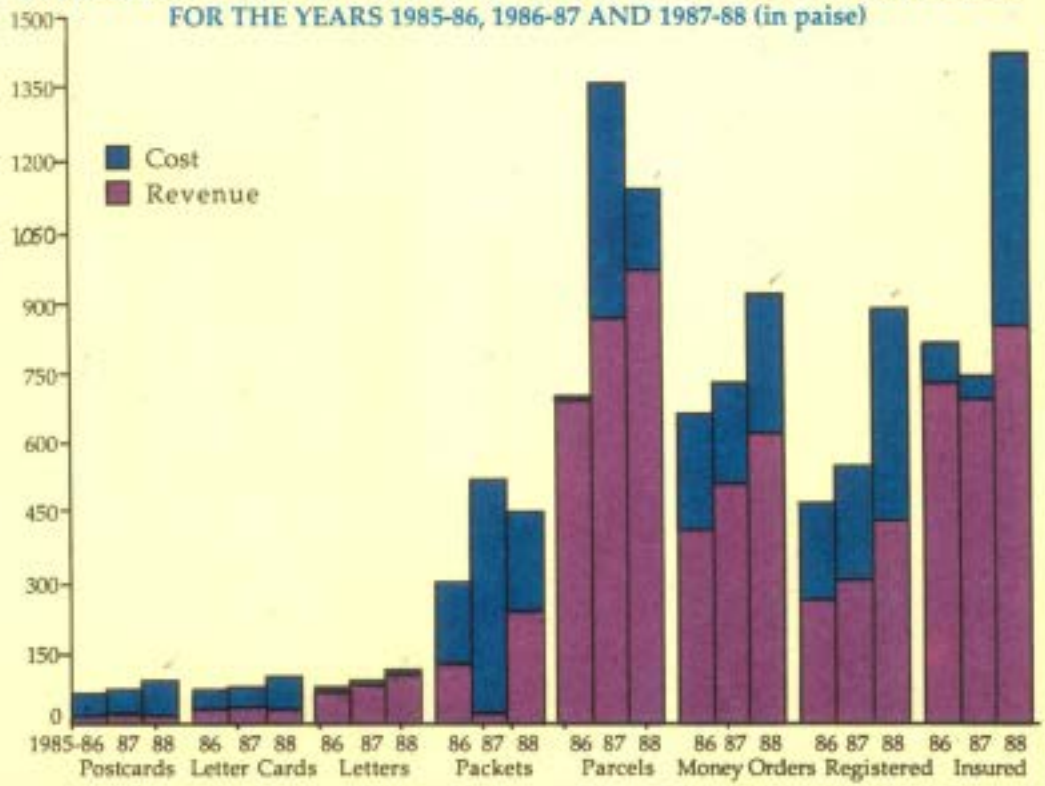

REVENUE AND EXPENDITURE OF SELECTED POSTAL ARTICLES FOR THE YEARS 1985-86-87 AND 1987-88

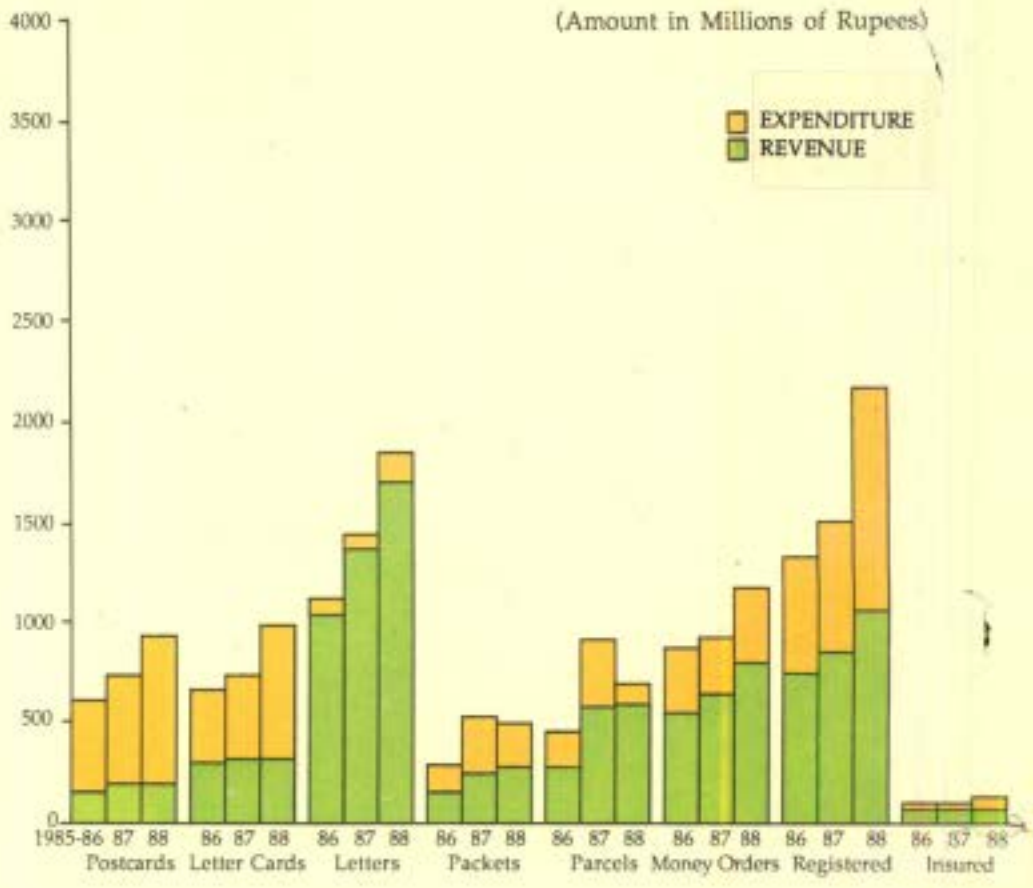

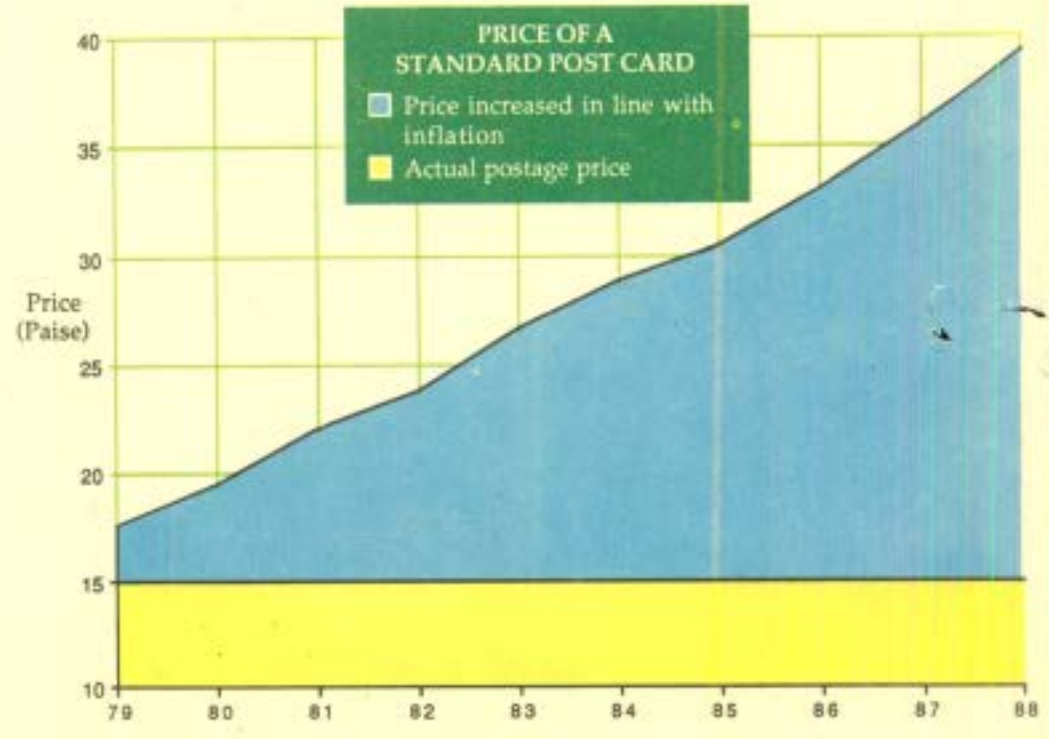

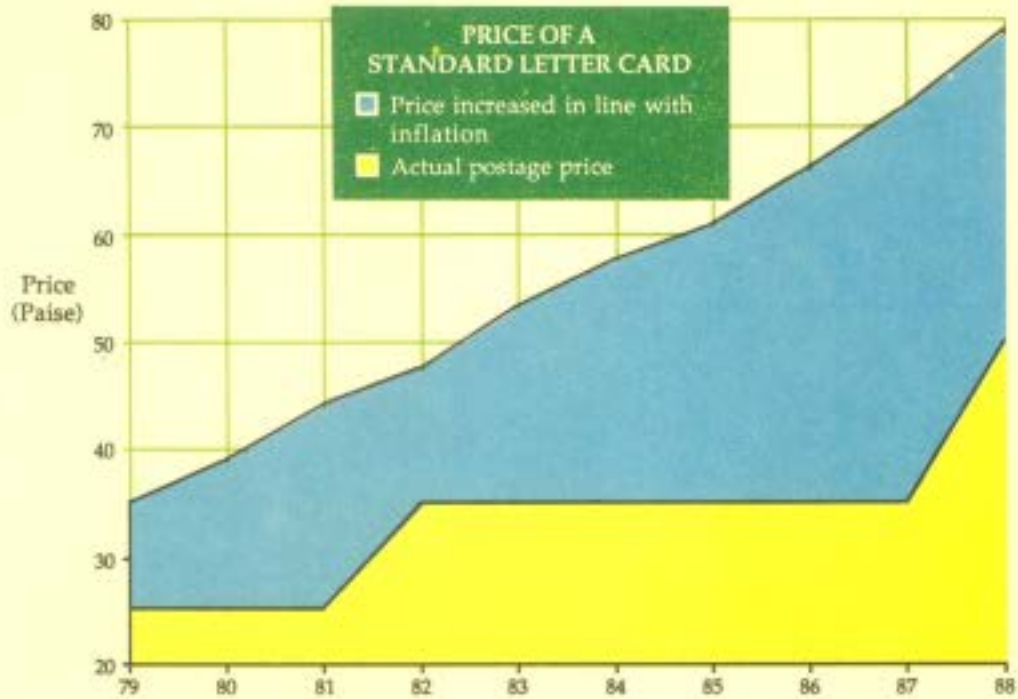
PRICE OF A
STANDARD LETTER CARD
Price increased in line with inflation
Actual postage price
Price (Paise)
80
70
60
50
40
30
20
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

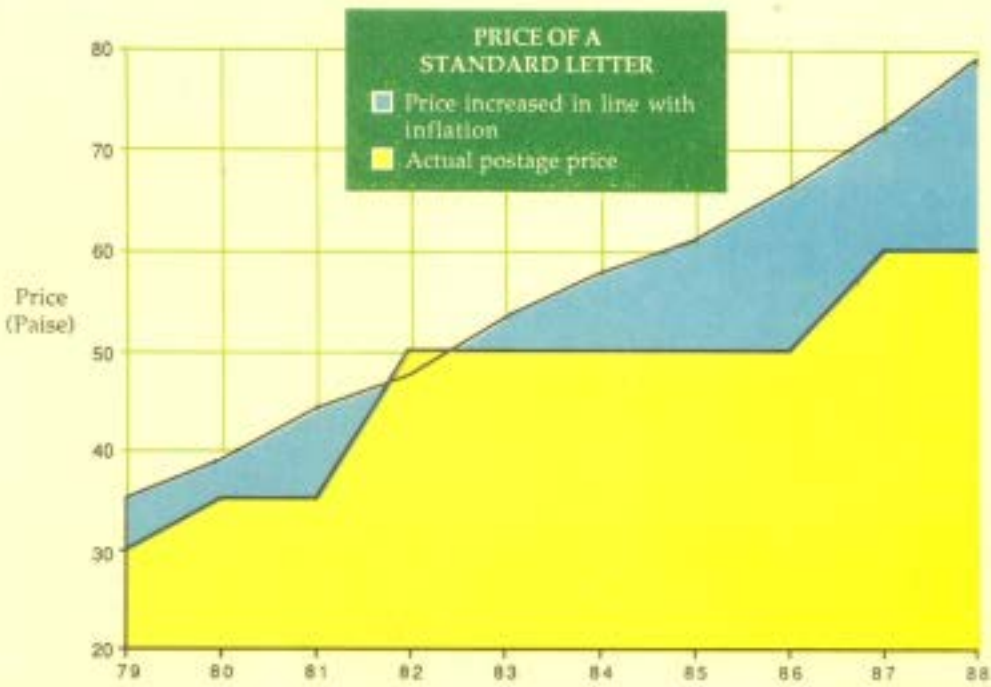
PRICE OF A
STANDARD LETTER
Price increased in line with inflation
Actual postage price
Price (Paise)
80
70
60
50
40
30
20
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

The total revenue earned during the year 1987-88 was Rs. 6429.8 million, which represented an increase in gross terms of Rs. 854.8 million and, in percentage terms, of 15.3 over the revenue earned during 1986-87. The revenue realised was 98.2% of the revenue estimated for the year

Revenue 1987-88

	Amount (in millions of Rs.)	Percentage
• Sale of stamps	3812.1	59.3
• Postage realised in cash	1129.3	17.6
• Commission on account of Money Orders and Indian Postal Orders	799.6	12.4
• Other receipts	688.8	10.7

Expenditure 1987-88

	Amount (in millions of Rs.)	Percentage
• General Administration	686.7	8.24
• Operation	5657.5	67.85
• Agency Services	258.3	3.10
• Others	1736.0	20.81

The gross revenue expenditure in important categories is given below:

	Amount (in millions of Rs.)	Percentage
• Pay & Allowances, Contingencies, Interim Relief & other items	830.58	80.85
• Accounts and Audit	23.10	2.25
• Pensionary charges	96.34	9.38
• Stamps, Post Cards	20.78	2.02
• Stationary & Printing etc.	88.2	0.86
• Maintenance of assets, etc.	51.9	0.51
• Petty works	12.4	0.12
• Conveyance of mails (Payment to Railways and Air Mail Carriers)	411.9	4.01

The net working expenses during the year 1987-88 were Rs. 8338.5 millions, against the estimated expenditure of Rs. 7896.2 millions, representing an increase of Rs. 442.3 millions, which is mainly due to increase in the rates of minimum wages following a Supreme Court decision and revision of minimum pension and family pension.

The deficit for 1987-88 was Rs. 1908.7 million which was less by Rs. 255.6 million than the deficit for the year 1986-87 (Rs. 2164.3 million)

The gross outlay on fixed assets during the year was Rs. 305.2 million (96.76% on land and buildings and 3.24% on apparatus, plants and others). Capital outlay on fixed assets rose to Rs. 3266.8 million at the end of the year. The net progressive capital outlay to the end of the year financed from General Revenues was Rs. 2644.6 millions.

REVENUE AND EXPENDITURE FOR THE YEAR 1987-88

REVENUE Rs. 6429.8 MILLIONS

Others	10.73%
Commission on Money Orders and Indian Postal Orders	12.44%
Postage in cash	17.56%
Sale of stamps	59.27%

EXPENDITURE Rs. 8338.5 Millions

Agency Services	3.10%
General Administration	8.24%
Others	20.81%
Operations	67.85%

CAPITAL OUTLAY

FOR 1987-88 Rs. 305.2 Millions

Apparatus Plants and others	0.13%
Mail Motor Vehicles	3.11%
Land and Building	96.76%
RMS VANS	NIL

UPTO 1987-88 Rs. 3266.8 Millions

Mail Motor Vehicles	1.12%
RMS VANS	2.64%
Apparatus Plants and others	3.97%
Land and Building	92.27%

ACTIVITIES (1.4.1988 - 31.12.1988)

Expansion of the postal network continued largely in rural areas and industrial project areas. 60 new Branch Post Offices and 23 Departmental Sub-Offices were opened in different parts of the country. A further liberalisation was made in the policy of opening new rural post offices by dispensing with the permissible limit of loss in monetary terms since such a limit was not consistent with the prescribed minimum revenue of 33-1/3% of the cost in normal areas and 15% of the cost in hilly, tribal and backward areas.

The new Panchayat Dak Sewak Scheme was given concrete shape and sound footing with the appointment of 3386 Dak Sewaks in different parts of the country. Under this scheme, Gram Panchayats/Village Councils which do not have a Post Office are given a monthly cash grant of Rs. 150/- for maintaining their own Dak Sewaks to provide postal facilities to the village. Necessary service linkages and liberalised commission on the sale of postage stamps and stationery are provided by the Department to these Gram Panchayats.

In order to increase the efficiency of mail transmission system, 55 mail motor vehicles were replaced to strengthen the existing fleet structure and also to modernize mail carriage in smaller towns. 24 vehicles were purchased exclusively for the Speed Post Service.

Continuing with the thrust on modernisation, efforts have been made to develop a lighter substitute to replace the heavier jute canvas bag used for conveying mails. High density polythylene material manufactured by the National Jute Manufacturing Corporation in collaboration with Jute Technological Laboratory is shortly to be tested in selected Post Offices.

In the field of philately, active preparations were on the stage INDIA 89 World Philatelic Exhibition. A set of two stamps commemorating the exhibition, depicting Bombay GPO and Bangalore GPO Buildings as examples of earlier and later architectural styles, was released on 9th October, 1988 on World Post Day. Another two stamps on markings (cancellations) of the R.M.S. and Dead Letter Office (now called Returned Letter Office) were released in December, 1988. Apart from these, 37 other stamps were released during this period. The Department participated in three International Exhibitions - FINLANDIA-88, PRAGA-88 and OLYMPHILEX-88. In addition, two State level exhibitions were organised in Andhra Pradesh and Karnataka.

The Savings Bank Organisation took another step forward with the introduction of Kisan Vikas Patras with effect from 1.4.1988. The maturity period of this certificate is 5 years and the rate of interest is 12%. The maximum limit of deposit in the monthly income scheme was raised from Rs. 1 lakh to Rs. 2 lakhs in a single account and from Rs. 2 lakhs to Rs. 4 lakhs for joint account. In order to facilitate clearance of post office cheques, another 230 Head Post Offices were enrolled as full members of local Clearing Houses.

Training continued to receive importance as an input for development of human resources. A number of training courses were conducted by the Postal Staff College which included Management Development Programme, seminars on Mail Transmission, Postal Modernisation, Personnel Policy and Organizational Structure and International Mail Circulation.

SINCE 1985: SUMMARY OF ACHIEVEMENTS.

A Public Utility.

The Department of Posts has continued to expand its network to provide services to 120 million homes in the country in spite of resources constraint. During the period of three years ending 1.4.88, 898 new post offices were opened taking the total number of post offices in the country to 1,44,829 post offices of which 1,28,829 are in the rural areas. Each post office serves on an average an area of 22.69 sq.kms. and a population of 4731. The Department has planned to open 6000 new post offices during the 7th Plan (1985-90). During the year 1988-89 and 1989-90 the Department has proposed to open about 5000 post offices out of the planned 6000 post offices. In order to facilitate opening of more post offices in the rural areas, the norms for opening of post offices have been liberalised w.e.f. 19.12.1987. Further liberalisation has also been made by dispensing with the maximum permissible limit of loss for opening of post offices in the rural areas. In tune with the decentralised administrative set up of Panchayats, the department has introduced a new scheme called "PANCHAYAT DAK SEWAK SCHEME" whereby panchayats/village councils which do not have a post office are given a monthly cash grant of Rs. 150/- for maintaining their own Dak Sewaks. To provide postal facilities to the panchayats, 3386 Dak Sewaks have been appointed in different parts of the country. The final goal is to cover each one of the remaining 74000 panchayat villages as early as possible.

Mail Services.

The Department of Posts handles nearly 5000 million pieces of mail during a year. The mail is collected from 4,81,757 letter boxes in the country out of which 4,01,156 are in rural areas and 80601 are in urban areas. By making use of its long tradition and expertise in the area of transmission and delivery of mail the Department introduced a guaranteed delivery service in 1986 called "SPEED POST" as a cheaper and more reliable alternative to the growing private courier services. Starting with only 7 centres in August 1986, it has been extended to 37 centres at the end of financial year 1987-88.

Using Modern Technology.

Though most of the activities of the Department of Posts are carried out in the traditionally manual way, the Department has been making efforts to bring in modern technology in order to increase its productivity and hold the price line of its products and services. Multi-purpose machines for use at the counters, digital weighing scales to weigh articles, compute postage and issue receipts to the customers, stamp cancelling machines to cancel postage stamps are under process of development and are likely to be introduced for use shortly. The Department is also cautiously introducing computerisation in certain areas of its operations which involve complex manual calculations with due regard to the ticklish question of man-power displacement.

Motor Vehicles.

For providing an efficient mail service, the Department owns a fleet of vehicles numbering 1053 at the end of financial year 1987-88. During the last four years, 357 motor vehicles were purchased either to replace the ageing vehicles or as new additions to the fleet.

Postal Buildings.

On 1.4.1988 the Department of Posts owned 3473 buildings for housing post offices, mail offices and administrative offices and 20845 quarters for employees. During the preceding four years 322 buildings were constructed for various offices and 4217 quarters were built for the employees.

Agency Services.

The Department of Posts plays an important role in mobilising small savings for funding the developmental activities of the country. At the end of the financial year 1987-88, the outstanding balance in all types of saving instruments was Rs. 284007 million which represented a 110% increase over the balance at the end of 1983-84. Postal Life Insurance also registered a significant gain during the last four years. The number of policies increased from 1.08 millions at the end of 1983-84 to 1.36 millions at the end of 1987-88 representing an increase of 25.58%. The total sum assured on the policies also increased from Rs. 8094 million at the end of 1983-84 to Rs. 14393 million at the end of 1987-88 representing an increase of 77.82%.

TABLE I
Financial Working

(Rupees in Crores)

	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
Receipts	434.54	444.41	476.84	557.50	642.98
Expenditure					
General Administration	41.15	46.36	53.82	60.28	68.67
Operation	417.63	463.00	520.15	664.22	754.22
Agency Services	21.11	24.89	23.89	27.60	32.81
Research & Development	-	-	-	-	-
Accounts and Audit	13.50	14.94	15.87	19.56	23.10
Engineering Maintenance	9.84	11.40	11.26	12.18	13.03
Amenities to Staff	5.95	7.09	7.35	8.56	7.93
Pensionary Charges	32.89	37.06	49.10	61.95	96.34
Stamps, Stationary & Printing	28.09	28.72	43.23	44.39	30.36
Depreciation	2.04	2.20	2.99	3.81	4.36
Supplementary Depreciation	-	-	-	-	-
International Cooperation	0.28	0.31	0.39	0.55	0.66
Social Security & Welfare Programmes	0.08	0.10	0.14	0.09	0.12
Credits to Working Expenses	64.79	67.41	87.80	129.26	197.75
Net Working Expenses	507.77	568.66	640.39	773.93	833.85
Net Receipts	(-)73.23	(-)124.25	(-)163.55	(-)216.43	(-)190.87
Dividend to General Revenues	9.07	11.84	-	-	-
Surplus (+)/Deficit(-)	(-)82.30	(-)136.09	(-)163.55	(-)216.43	(-)190.87

TABLE 2
Capital outlay during and upto the end of 1987-88
Fixed Assets
Other Assets

(Rs. in Crores)

1.	Land	3.44
2.	Buildings	31.07 26.09 270.36
3.	Railway Mail Vans owned by Post Offices	-
4.	Apparatus and Plant	8.61 0.04
5.	Motor Vehicles	12.97 0.95
6.	General Administration/Direction & Execution Establishment & other charges etc.	3.66 -
7.	Other Expenditure	- -
8.	Gross Fixed Assets	0.01 30.52 326.68
9.	Deduct-Receipts and Recoveries on Capital Account	0.10 0.51
10.	Total Fixed Assets (i.e. total of items 1 to 7)	30.42 326.17
11.	Deduct-Expenditure met from Posts and Telegraphs Capital Reserve Fund	-
12.	Deduct-Amount of Contribution from Revenue	1.29 -
		27.86

13.	Deduct-Depreciation on historical cost transferred from Revenue	4.35 30.57
14.	Total Deductions (i.e. total of items 11 to 13)	4.35 59.72
15.	Net Fixed Assets (i.e. item 10 minus 14)	26.07 266.45
16.	Total Dividend bearing Capital outlay	26.07 266.45
17.	Deduct-Portion of Capital outlay financed from ordinary Revenue	- 1.05
18.	Total Capital outlay (Voted) (i.e. item 16 minus 17)	26.07 265.40

Note : Figures in bold are for Total Capital outlay.

TABLE 3
Number of Post Offices As On 31st March, 1988

	States/Union Territories	Urban	Rural	Total	Population served by a post Office (1981 census)	Area served by a post Office (sq. kms.)
1.	Andhra Pradesh	1448	14678	16126	3321	17.05
2.	Assam	256	3092	3348	5943	23.43
3.	Arunanchal Pradesh	9	231	240	2632	348.92
4.	Bihar	580	10389	10969	6374	15.85
5.	Goa	56	163	219	4601	16.90
6.	Gujarat	767	7784	8551	3986	22.92
7.	Haryana	297	2155	2452	5270	18.03
8.	Himachal Pradesh	98	2335	2433	1759	22.88
9.	Jammu & Kashmir	165	1294	1459	4104	152.32
10.	Karnataka	1301	8206	9507	3906	20.17
11.	Kerala	680	4088	4768	5338	8.15
12.	Madhya Pradesh	1078	9505	10583	4930	41.90
13.	Maharashtra	1526	10116	11642	5393	26.34
14.	Manipur	8	534	542	2621	41.19
15.	Meghalaya	30	387	417	3203	53.78
16.	Mizoram	38	258	296	1668	71.21
17.	Nagaland	19	238	257	3015	64.50
18.	Orissa	541	7003	7544	3495	20.64
19.	Punjab	450	3280	3730	4501	13.50
20.	Rajasthan	814	8831	9645	3552	35.48
21.	Sikkim	13	114	127	2491	55.87
22.	Tamil Nadu	2087	9816	11903	4067	10.92
23.	Tripura	47	574	621	3306	16.88
24.	Uttar Pradesh	2093	16343	18436	6013	17.97
25.	West Bengal	1092	7116	8208	6649	10.81
	Union Territories					
1.	Andaman & Nicobar Islands	12	68	80	2359	103.51
2.	Chandigarh	38	6	44	10263	2.59
3.	Delhi	412	115	527	11803	2.81
4.	Dadra & Nagar Haveli	-	30	30	3456	16.37
5.	Daman & Diu	4	13	17	4646	6.59
6.	Lakshadweep	-	10	10	4025	3.20
7.	Pondicherry	41	57	98	6168	5.02
	Total:	16,000	128829	144829	4731	22.69

TABLE 4
SAVINGS BANK

I. General	1983-84	1984-85	1985-86	1986-87	1987-88
1. No. of Post Offices doing SB Work	144508	144615	144129	143232	144084
2. No. of Post Offices doing SB Work in rural areas	129116	128694	128694	126582	127223
3. No. of Accounts of savings all types (in million)	65.79	71.95	90.85	77.50	73.92
4. Outstanding balances in all forms of National Savings (Rs. in million)	135240	172070	214570	247540	284007
II. Details of Accounts					
1. SB	39161353	41339798	41741882	42196243	43869397
2. PPF	21273	25657	26410	29542	41993
3. CTD	4639150	4634302	5171638	5455395	5195223
4. RD	20525982	24601853	42727050	28647935	23604282
5. TD	1353599	1313888	1154821	1170339	1015782
6. FD*	39048	38367	37877	37372	196929
Total	65790405	71953865	90859678	77536826	73923606
III. Outstanding					
Balance in Savings A/cs. (Rs.in millions)	89529.50	101696.80	114516.80	113020.00	115763.20
Outstanding Balance in all Types of certificates (in million)	45708.90	70503.00	98870.20	134520.60	167903.0
Outstanding balance in PPF A/cs. (in million)	-	-	-	-	341.70

* includes Monthly Income Scheme and National Saving Scheme for 1987-88.

TABLE 5
Postal Life Insurance

Year	New Business		Total Business in force		Life Insurance Fund (Rs. in crores)
	No.of Policy	Sum assured (Rs. in crores)	No. of Policy	Sum assured (Rs. in crores)	
1978-89	1,01,707	69.6	6,34,444	315.5	85.7
1979-80	1,08,975	83.1	7,31,734	394.9	105.7
1980-81	1,20,170	102.1	8,36,455	491.8	129.7
1981-82	1,12,703	106.9	9,30,007	590.4	157.3
1982-83	1,05,157	108.4	10,06,910	685.3	190.6
1983-84	1,17,473	143.0	10,84,172	809.4	223.9
1984-85	1,11,637	153.0	11,56,497	942.8	260.6
1985-86	1,01,168	160.4	12,15,981	1070.9	307.2
1986-87	1,03,253	179.3	12,81,425	1227.6	368.9
1987-88	1,19,866	232.9	13,61,532	1439.3	446.1

TABLE 6

Personnel Actual Strength (including those on deputation and training outside the Department) as on 31.3.1988

Gazetted

	Group A'	Group B'	Total
Secretary (Posts)	1	-	1
Members, Postal Services Board	4	-	4
Secretary, Postal Services Board	1	-	1
Indian Postal Service			
Senior Administrative Grade	64	-	64
Junior Administrative Grade	120	-	120
Senior Time Scale	252	-	252
Junior Time Scale	92	-	92
Postal Superintendent Service	-	615	615
Postmaster's Service	16	177	193
P&T Accounts & Finance Service			
Senior Administrative Grade	1	-	1
Junior Administrative Grade	10	-	10
Senior Time Scale	22	-	22
Junior Time Scale	15	-	15
Accounts Officers	-	320	320
Central Secretariat Service			
Junior Administrative Grade	2	-	2
Senior Time Scale	3	-	3
Junior Analysts	-	3	3
Section Officers	-	25	25
Private Secretaries (Grade A)	-	4	4
Senior Personal Assistance (Grade B)	-	16	16
Desk Officers	-	12	12
Civil Wing			
Chief Engineer	1	–	1
Group 'A'	62	-	62
Group 'B'	-	191	191
Other General Central Services	128	102	230
Total	794	1465	2259

TABLE 6 contd.

Non-Gazetted

	Group C'	Group D'	Total
Directorate			
Audit & Accounts	78	12	90
Others	397	135	532
Postal			
Audit & Accounts	5008	515	5523
Others	191609	33747	225356
Railway Mail Service	27986	19615	47601
Mail Motor Service	2178	652	2830
Returned Letter Offices	821	98	919
Postal Life Insurance	210	32	242

Stores	1225	1714	2939
Training Centres	102	165	267
Civil Engineering Wing	1468	803	2271
P&T Dispensaries	331	318	649
Total	231413	57806	289219
Extra Departmental			298320

SUMMARY

	Gazetted	Non-Gazetted	Others	Total
Departmental	2259	289219	-	291478
Extra Departmental	-	-	298320	298320
Total	2259	289219	298320	589798

TABLE 7
Number of Employees - Scheduled Castes/Tribes as on 1-1-1988

	Scheduled Castes	Percentage to Total No. of employees	Scheduled Tribes	Percentage to Total No. of employees
Group 'A'	68	12.85	23	4.34
Group 'B'	151	16.61	60	6.60
Group 'C'	39977	18.24	12050	5.49
Group 'D' (Excluding sweepers)	10541	20.52	3131	6.09
Group 'D' (Sweepers)	855	65.16	47	3.58

51592 15311

TABLE 8
Number of Employees - Ex-servicemen as on 31-3-1988

Class	Ex-service men	Percentage to Total No. of employees	Disabled Ex-service man	Percentage to Total No. of employees
Group 'A'	-	-	-	-
Group 'B'	-	-	-	-
Group 'C'	2256	0.97	49	0.02
Group 'D'	731	1.26	19	0.03

E R R A T A

Page No.	Para	Line	Col.	For	Read
25	Expansion of Postal Postal Network	20	1	Whichare to opened	Which are to be opened
		6	2	is not less than 1500 in hilly, back-ward & tribal areas	is not less than 1500 in hilly, backward & tribal areas and 3000 in normal rural areas
33	Staff strength (Graph relating to Gazetted/- Non-Gazetted and Extra-Departmental staff)			Colour Code Red - Non Gazetted Green - Extra Depart-mental	Colour Code Red - Extra Departmental Green - Non Gazetted
44	Activites	27	2	5 years	5½ years